वर्ष-10//अंक-18// मार्च 2023
ISSN 2454–5805
₹20/-

आम आदमी पत्रिका®

एक आम इंसान की सोच

RNI NO.: CHHHIN/2013/50684

कांग्रेस का महाधिवेशनः सत्ता संग्राम की कठिन चुनौतियां

कैसा होगा राजनीतिक भविष्य?

www.aamaadmi.in

Chai Signal

Taste Our Delicious Food at your Doorstep!

Order on SWIGGY zomato

www.chaisignal.com

Shop No.24, Katora Talab Garden, Raipur (C.G.)

Follow Us:

आम आदमी पत्रिका
वर्ष-10//अंक-18// मार्च 2023

प्रबंध संपादक : उमेश के बंसी
सर्कुलेशन इंचार्ज : प्रकाश बंसी
रिपोर्टर : नेहा श्रीवास्तव
कंटेंट राईटर : प्रशांत पारीक
क्रिएटिव डिजाइनर : देवेन्द्र देवांगन
मैग्ज़ीन डिज़ाइनर : युनिक ग्राफिक्स
मार्केटिंग मैनेजर : किरण नायक
एडमिनिस्ट्रेशन : निरूपमा मिश्रा
अकाउंट असिस्टेंट : प्रियंका सिंह
ऑफिस कॉर्डिनेटर : योगेन्द्र बिसेन

प्रधान कार्यालय
965/1 कक्कड़ चौक, श्याम नगर रोड,
कटोरा तालाब,रायपुर, छत्तीसगढ़
फोन : 0771-4044047
ईल : khabar@aamaadmi.in
कार्यालय
प्लाट नं.118, कंचन बाग, राजनांदगांव

प्रकाशक
उमेश कुमार बंसी, क्वाटर नंबर 10, एम.एम. रियल स्टेट कॉलोनी, अमलीडीह, रायपुर (छत्तीसगढ़) से प्रकाशित एवं मुद्रित

विशेष- इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में दिये गए विचार, लेखकों के अपने है। इसमें संपादक / मुद्रक की सहमति अनिवार्य नहीं है। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में संपादक / मुद्रक जिम्मेदार नहीं होगा। इस पत्रिका से संबंधित किसी भी विवाद के लिए सुनवाई क्षेत्र रायपुर न्यायालय होगा।

अनुक्रमणिका

मार्च 2023

इस अंक में

छत्तीसगढ़ की खेल अकादमियों ने रचे सफलता के कीर्तिमान

रायपुर. छत्तीसगढ़ में खेल गतिविधियों के विकास एवं खेल प्रतिभाओं के तराशने के लिए राज्य शासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों के अंतर्गत विगत चार वर्षो के दौरान स्थापित विभिन्न खेल अकादमियों ने सफलता के नये कीर्तिमान स्थापित किए हैं. 08

प्रसूति सहायता राशि को १० हजार से बढ़ाकर २० हजार रूपए किए जाने का अनुमोदन 11

मंत्री डॉ. डहरिया की अध्यक्षता में असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल की बैठक सम्पन्न

गौमूत्र से बने जैविक कीटनाशक 15

रायपुर. राज्य में गौमूत्र से जैविक कीटनाशक ब्रम्हास्त्र और फसल वृद्धिवर्धक जीवामृत का उत्पादन और उपयोग खेती में होने लगा है.

सोनू सूद ने लॉन्च की भारत की सबसे बड़ी थाली 19

एक्अर सोनू सूद का आज हर कोई फैन है. उन्होंने जिस तरह कोरोना महामारी में लोगों की मदद की, उसके लिए आज भी लोग उन्हें सम्मानित करते हैं.

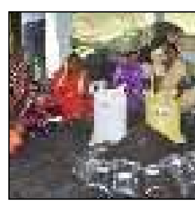

भूपेश सरकार की योजनाओं से ग्रामीण महिलाओं के सपनों को लगे पंख, 20

रायपुर. छत्तीसगढ़ में गोबर से लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है. गोबर से वर्मी कम्पोस्ट के साथ-साथ पेंट और बिजली भी तैयार किया जा रहा है.

अडानी के शेयरों में गिरावट का असर, एलआईसी ने ५० दिनों में गंवाए ५० हजार करोड 23

सरकारी बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की गिनती शेयर बाजार के बड़े इन्वेस्टर्स में होती है.

मसालों की खेती में छत्तीसगढ़ की बन रही देश में नई पहचान 34

छत्तीसगढ़ में मसालों की खेती का दायरा बढ़ते जा रहा है. राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों का खेती- किसानी के क्षेत्र में असर दिख रहा है.

कांग्रेस का महाधिवेशनः सत्ता संग्राम की कठिन चुनौतियां

कैसा होगा राजनीतिक भविष्य?

उमेश के बंसी
(प्रबंध संपादक)

देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के रायपुर में सम्पन्न तीन दिन के पूर्ण महाधिवेशन से पार्टी से देश को क्या लाभ होगा, होगा भी या नहीं, इसको लेकर सियासी हल्को में अपने अपने ढंग से आकलन किया जा रहा है.

इस महाधिवेशन में जो मुख्य बिंदु उभर कर आए हैं, वो हैं- कांग्रेस ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में पूरी ताकत से लड़ने का संकल्प जताया है. दूसरा, पार्टी भाजपा व साम्प्रदायिक ताकतों को परास्त करने के लिए हर संभव कोशिश करेगी. तीसरा, सामाजिक न्याय के मुद्दे को पूरी तवज्जो देगी. चौथा विवादास्पद उद्योगपति गौतम अडानी के बहाने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर सीधा हमला जारी रहेगा. पांचवा, पार्टी में युवाओं को आगे लाने की पूरी कोशिश होगी. छठा, कांग्रेस समान विचारों वाले विपक्षी दलों को एकजुट करेगी तथा सातवां पार्टी का अध्यक्ष कोई भी हो, वास्तविक कमान गांधी परिवार के हाथ में ही रहेगी. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का यह 85वां महाधिवेशन था, जिसमें सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों से कांग्रेस नेता व प्रतिनिधि शामिल हुए. आजादी के पहले तक कांग्रेस का महाधिवेशन अमूमन हर साल होता था. लेकिन स्वतंत्रता के बाद इसका उत्साह घटता गया और पार्टी सत्ता केन्द्रित ज्यादा हो गई.

रायपुर में हुआ यह अधिवेशन भी पांच साल बाद हुआ है. इसे यूं भी समझा जा सकता है कि कांग्रेस आम चुनाव के पहले ही महाधिवेशन करती है. पिछला महाधिवेशन 2018 में नई दिल्ली में हुआ था. महाधिवेशनों में इतना अंतराल निश्चित पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में कसावट पैदा करने में बाधक सिद्ध होता है. यह महाधिवेशन भी देश में मौजूदा राजनीतिक चुनौतियों, विद्वेष की राजनीति और आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर ही आयोजित किया गया था. इस महाधिवेशन में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी अब अपने दम पर विचार विमर्श और फैसले करने लगी है, लेकिन तीसरे और अंतिम दिन तक आते-आते यह बात साफ हो गई कि पार्टी में मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा निर्वाचित अध्यक्ष भले ही हो, वास्तविक कमान राहुल गांधी के हाथ में ही रहने वाली है.यह राहुल पर निर्भर है कि सफल 'भारत जोड़ो यात्रा' के बाद वह गुटों में बंटी और ऊपर से नीचे तक अंतर्कलह से जूझ रही कांग्रेस को किस तरह नियंत्रित और संचालित करते हैं.

'भारत जोड़ो यात्रा' से पार्टी को लाभ

महाधिवेशन में तकरीबन हर नेता ने 'भारत जोड़ो यात्रा' की तारीफ के पुल बांधे. इसमें राहुल भक्ति के साथ-साथ कार्यकर्ताओं में आई निराशा छंटने का शुभ संकेत भी था. माना गया कि राहुल की इस निर्बाध यात्रा से देश में विपक्ष के लिए अनुकूल वातावरण बना है. लिहाजा राहुल अब देश में पूर्व से पश्चिम को जोड़ने के लिए पैदल यात्रा करेंगे. इससे कांग्रेस के पक्ष में माहौल और सघन होगा.

महाधिवेशन में पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के भाषण का यह अर्थ निकाला गया कि वो अब रिटायर होना चाहती हैं. लेकिन कार्यकर्ताओं में इसका गलत संदेश जाने की आशंका के चलते दूसरे ही दिन ऐसी किसी संभावना का खंडन कर दिया गया.

37 हजार से अधिक चिटफंड निवेशकों को 30 करोड़ से अधिक राशि लौटायी गयी

रायपुर. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर अनियमित वित्तीय कंपनियों (चिटफण्ड कंपनियों) एवं उनके संचालको के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है. मुख्यमंत्री के निर्देश पर अनयिमित वित्तीय कंपनियों (चिटफण्ड कंपनियों) के संचालन को राज्य में पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है. चिटफंड कंपनियों की नीलामी से प्राप्त राशि 30 करोड़ रूपये, 37 हजार 325 निवेशकों को वापस लौटायी जा चुकी है.

वर्ष 2015 से वर्ष 2023 (31 जनवरी) तक 208 अनियमित वित्तीय (चिटफण्ड) कंपनियों के विरूद्ध 460 प्रकरण पंजीबद्ध कर 536 डायरेक्टरों एवं 119 पदाधिकारियों कुल 655 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. न्यायालय द्वारा 84 प्रकरणों में 44 अनियमित वित्तीय कंपनियों की चिन्हित सम्पत्तियां जिनकी अनुमानित कीमत 76 करोड़ 32 लाख 40 हजार 870 रूपये की कुर्की का अंतिम आदेश किया गया है. 54 प्रकरणों में 32 अनियमित वित्तीय कंपनियों के 52 करोड़ 04 लाख 48 हजार 406 रूपये की नीलामी / वसूली / राजीनामा की कार्यवाही पूर्ण की जाकर राशि शासन के खाते में प्राप्त हो चुकी है. 30 प्रकरणों में 14 अनियमित वित्तीय कंपनियों के चिन्हित सम्पत्तियां जिसकी अनुमानित कीमत 24 करोड़ 27 लाख 92 हजार 646 रूपये की न्यायालय से अंतिम आदेश के बाद नीलामी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.

इसी तारतम्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअली कार्यक्रम में चिटफंड कंपनियों में निवेश करने वाले दुर्ग जिले के 3 हजार 274 निवेशकों को 2 करोड़ 56 लाख रुपए की राशि लौटायी . इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में चिटफंड कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों को अब तक लगभग 30 करोड़ रुपए की राशि लौटाई जा चुकी है. हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में ठगी करने वाली चिटफंड कंपनियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई कर रही है. ठगी करने वाली चिटफंड कंपनियों की सम्पत्तियों को कुर्क कर निवेशकों को राशि वापस की जा रही है. उन्होंने कहा कि चिटफंड कंपनियों ने छत्तीसगढ़ में भोले-भाले लोगों को लालच देकर जीवनभर की कमाई लूट ली. हमारी सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि निवेश करने वालों को उनका पैसा वापस मिल जाये.

देश में छत्तीसगढ़ ही एकमात्र राज्य है जो निवेशकों को उनका पैसा वापस दे रहा है. कार्यक्रम में दुर्ग एसपी अभिषेक पलल्व ने बताया कि जिले में अब तक चिटफंड कंपनियों के 126 डायरेक्टर और 8 पदाधिकारियों की गिरफ्तार किया गया है.

वर्चुअल कार्यक्रम में दुर्ग के उपरवारा निवासी घनश्याम साहू ने मुख्यमंत्री से बात करते हुये कहा कि उन्होंने 2 एकड़ जमीन बेचकर चिटफंड में पैसा लगा दिया था. रकम डूबने के बाद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पैसा वापस मिलेगा. लेकिन आपकी सरकार के प्रयासों से आज मुझे 9 लाख रूपये वापस मिल रहा है. इससे मेरा पूरा परिवार बेहद खुश है. खुर्सीपार की तीजनबाई ने मुख्यमंत्री को बताया कि आज मेरा 3 लाख रूपये वापस मिल रहा है. अब मैं अपने बच्चों की शादी आसानी से कर पाउंगी. मुझे पूरी उम्मीद थी कि आपके रहते मेरा पैसा जरूर वापस मिलेगा .

कार्यक्रम में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, पीएचई मंत्री गुरू रुद्र कुमार, विधायक अरूण वोरा, मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा, एसपी अभिषेक पल्लव सहित हितग्राही उपस्थित रहे.

भारत के स्टार्टअप का कमाल, दुनिया में पहली बार चिप्स के पैकेट्स को रिसायकल करके बने सनग्लासेस

पुणे की कंपनी ने किया यह कमाल दुनिया में पहली बार हुआ है यह

घर पर परिवार के साथ मजा करना हो या दोस्तों के साथ कहीं ट्रेवल, कोल्डड्रिंक के साथ कुरकुरे-चिप्स खाए बिना कुछ भी पूरा नहीं होता है. लोग बैठे-बैठे कई पैकेट्स चिप्स-कुरकुरे खा लेते हैं. लेकिन खाने के मजे में हम भूल जाते हैं कि इन चिप्स के पैकेट्स, जे कचरे में जाते हैं, वे हमारे

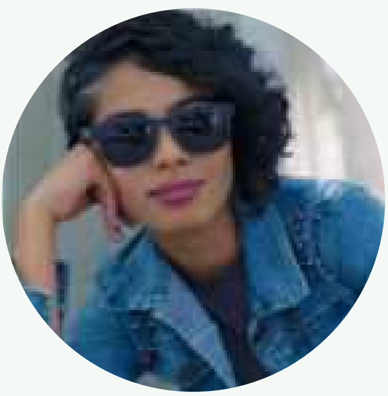

पर्यावरण के लिए कितने हानिकारक हैं.

मल्टी-लेयर प्लास्टिक से बने ये चिप्स पैकेट्स नॉन-बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जिसका मतलब है कि इन्हें गलने में लाखों-करोड़ों साल लगेंगे. प्लास्टिक का कचरा हमेशा चिंता का कारण रहा है, लेकिन एक भारतीय कंपनी ने अब चिप्स के पैकेट्स को रिसायकल करके इनसे को धूप के चश्मे (सनग्लासेस) बनाने का एक तरीका खोज लिया है.

आशया ने किया यह इनोवेशन

पुणे की एक कंपनी आशया ने दो साल के शोध के बाद अपनी छोटी सी लैब में बड़ी सफलता हासिल की है. उन्होंने मल्टी-लेयर प्लास्टिक (एमएलपी) को डिग्रेड करने और चिप्स के पैकेटों को रीसायकल करके ट्रेंडी सनग्लासेस बनाने का एक तरीका खोज लिया, जो यूवी-पोलराइज्ड, टिकाऊ और आरामदायक हैं.

स्टार्टअप के फाउंडर, अनीश मालपानी ने एमएलपी को धूप के चश्मे में बदलने की पूरी प्रक्रिया का खुलासा करते हुए ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया. उन्होंने कैप्शन लिखा कि यह अब तक का सबसे मुश्किल काम रहा है. आखिर में, चिप्स के पैकेट से बना दुनिया का पहला रिसायकल्ड धूप का चश्मा पेश करते हुए, यहीं भारत में!

बदलेगी कूड़ा बीनने वालों की जिंदगी

एक अन्य पोस्ट में, मालपानी ने साझा किया कि इस तकनीक के माध्यम से, वे लचीले पैकेजिंग मटेरियल से धूप के चश्मे के अलावा कोस्टर भी बनाएंगे. सबसे दिलचस्प बात यह है कि बिक्री से अर्जित राजस्व का उपयोग कूड़ा बीनने वालों और उनके परिवारों को बेहतर जीवन देने के लिए किया जाएगा.

मालपानी ने एक अन्य पोस्ट में साझा किया कि इस मल्टी-लेयर्ड प्लास्टिक कचरे को विश्व स्तर पर लगभग 0% के साथ रिसायकल करना असंभव माना जाता है. समुद्र में 80% कचरा यह प्लास्टिक पैकेजिंग है.

पत्रकारिता का उद्देश्य समाज की बुराईयों को दूर कर जागरूकता लाना है: मंत्री गुरू रूद्रकुमार

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामोद्योग मंत्री शामिल हुए श्रमजीवी पत्रकार संघ संभागीय पत्रकार सम्मेलन मे

रायपुर. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं ग्रामोद्योग और मुंगेली जिले के प्रभारी मंत्री गुरू रूद्रकुमार 08 मार्च को छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ संभागीय सम्मेलन में शामिल हुए. सम्मेलन का आयोजन मुंगेली के डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में किया गया था. कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों के द्वारा मंत्री गुरू रूद्रकुमार का भव्य स्वागत किया गया. मंत्री गुरू रूद्रकुमार ने छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर नमन किया और प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री गुरू रूद्रकुमार ने कहा कि लोकतंत्र में मीडिया की विशेष भूमिका रहती है, पत्रकार आलोचना के माध्यम से गलतियां सुधारने का अवसर प्रदान करते है. पत्रकार एक तरह से समाज को जागरूक करता है. समाज के लोगों को एक पत्रकार विभिन्न क्षेत्रों की जानकारियां देता है, जिससे गांव के लोग किसान एवं मजदूर वर्ग के लोग भी जानकारी पाकर अपने जीवन में आगे बढ़ पाते हैं और जीवन में कई कार्यों में आगे बढ़कर अपने जीवन को बेहतर करते हैं. वास्तव में पत्रकार हम सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं. पत्रकारिता का उद्देश्य समाज में व्याप्त बुराईयों को दूर करने और लोगों में जागरूकता लाना है. अगर लोग जागरूक होंगे तो सरकार जागृत होगी और सरकार जब जागरूक होगी तो लोगों के लिए भी बहुत कुछ अच्छा करेगी. उन्होने कहा कि शासन-प्रशासन के संज्ञान में समय-समय पर कमियों को उजागर करें. वहीं अच्छाइयों की प्रशंसा भी जरूर करें. मंत्री गुरू रूद्रकुमार ने छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ की कार्यालय भवन की मांग पर आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया.

नगर पालिका परिषद मुंगेली के अध्यक्ष हेमेन्द्र गोस्वामी और पत्रकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष अरविन्द अवस्थी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया. श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष राजकुमार यादव ने स्वागत भाषण दिया. कार्यक्रम में श्रमजीवी पत्रकार संघ द्वारा मंत्री गुरू रूद्रकुमार को स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया.

इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि राजेश त्रिवेदी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती लेखनी सोनू चंद्राकर, जिला पंचायत सदस्य वशी उल्लाह खान, बिलासपुर कृषि उपज मंडी अध्यक्ष राजेन्द्र शुक्ला, कृषि उपज मण्डी मुंगेली के अध्यक्ष आत्मा सिंह क्षत्रिय, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति प्राधिकरण के सदस्य सुश्री रत्नावली कौशल, प्रतिष्ठित नागरिक राकेश पात्रे, सागर सिंह बैस, श्रीमती मायारानी सिंह सहित श्रमजीवी पत्रकार संघ के पदाधिकारीगण और स्थानीय पत्रकारगण उपस्थित थे.

छत्तीसगढ़ की खेल अकादमियों ने रचे सफलता के कीर्तिमान

कोविड की चुनौतियों के बावजूद चार सालों में राज्य में खुली कई खेल अकादमियां

खिलाड़ियों को तराशने के लिए बेहतर सुविधाओं के साथ बेहतर प्रशिक्षण भी

राज्य के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्पर्धाओं में बटोरे कई पदक

रायपुर. छत्तीसगढ़ में खेल गतिविधियों के विकास एवं खेल प्रतिभाओं के तराशने के लिए राज्य शासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों के अंतर्गत विगत चार वर्षों के दौरान स्थापित विभिन्न खेल अकादमियों ने सफलता के नये कीर्तिमान स्थापित किए हैं. इस दरम्यान आए कोरोना संकट के बावजूद राज्य में नयी खेल अकादमियों की स्थापना की तैयारियां एवं खेल-गतिविधियां निरंतर चलती रही हैं.

चार साल पहले जब राज्य में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में नयी सरकार बनी तब खेल-कूद के क्षेत्र में अपनी प्राथमिकताएं तय करने हुए शासन ने राज्य में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करते हुए आगे बढ़ाने का संकल्प लिया था. मुख्यमंत्री ने इसके लिए सभी तरह की विश्वस्तरीय अधोसंरचना के निर्माण का वादा किया था.

कोरोना संकट गहराने के ठीक पहले वर्ष 2019 के बाद रायपुर में गैर आवासीय फुटबॉल बालिका अकादमी और संकट छंटने के बाद 2021 में गैर आवासीय एथलेटिक अकादमी प्रारंभ कर दी गई. वर्ष 2022 में बिलासपुर आवासीय अकादमी / एक्सिलेंस सेंटर तथा रायपुर की तीरंदाजी आवासीय अकादमी का संचालन शुरू कर दिया गया.

वर्ष 2019 के बाद बिलासपुर में तीरंदाजी, हॉकी, एथलेटिक की आवासीय अकादमी / एक्सिलेंस सेंटर, 2021 में शिवतराई बिलासपुर में तीरंदाजी उपकेन्द्र, 2022 में बालिका कबड्डी अकादमी बिलासपुर एवं रायपुर में आवासीय तीरंदाजी अकादमी, गैरआवासीय फुटबॉल (बालिका) एवं गैर आवासीय एथलेटिक अकादमी प्रारंभ हुई.

वर्ष 2019 के पूर्व राज्य में केवल 02 गैरआवासीय अकादमी हॉकी एवं तीरंदाजी की स्वीकृति थी. परंतु इनका अकादमी के रूप में संचालन न होकर केवल नियमित प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में हो रहा था. गैर आवासीय हॉकी एवं तीरंदाजी अकादमी रायपुर के लिए वर्ष 2020 में निर्धारित चयन ट्रायल की प्रक्रिया पूरी कर नियमित रूप से अकादमी संचालन प्रारंभ हुआ.

अकादमी के खिलाड़ियों ने जीते कई पदक

वर्ष 2021 में शिवतराई तीरंदाजी उपकेन्द्र शुरू होने के बाद इस केन्द्र से कुबेर सिंह, विकास कुमार, संदीप, हेमंत, देवेन्द्र कुमार, पायल मरावी, तुलेश्वरी, आकाश राज, अजय कुमार का चयन विभिन्न नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए राज्य के दल हुआ. इन खिलाड़ियों ने पदक भी हासिल किए. उपकेन्द्र की उपलब्धियों के कारण साई द्वारा इसे खेलो इंडिया सेंटर के रूप में मंजूरी भी दी गई.

फुटबॉल गैरआवासीय बालिका की खिलाड़ी कु. किरन पिस्दा ने साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन प्रतियोगिता में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया तथा वे 2021 में भारतीय टीम के कैम्प के लिए चयनित भी हुईं. अकादमी की प्रियंका फुटान, भूमिका साहू, उर्वशी, संजना छूरा, नेहा वंशी, नीलिमा खाखा, देवंतिन, जागृति, ऋतु का चयन 19 वीं नेशन इनक्लुसन कप हेतु भी हुआ, जोकि नागपुर में आयोजित है.

बिलासपुर आवासीय अकादमी / एक्सिलेंस सेंटर के हॉकी खिलाड़ी आदित्य कुमार ने भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित जूनियर वर्ग के इंडिया असेंसमेंट कैंप बंगलुरू-2022 में भागीदारी की. पश्चिम बंगाला में जनवरी-2023 में आयोजित ऑल इंडिया हॉकी टूर्नामेंट में अकादमी की गीता यादव, संपदा, मम्तेश्वरी, दामिनी, जान्हवी, रूखमणी मधु सिदार ने चयनित होकर पदक अर्जित किया है. एथलेटिक खिलाड़ी अंकित अहलावत ने नेशनल जूनियर मीट प्रतियोगिता आंध्रप्रदेश में कांस्य पदक प्राप्त किया है. एथलेटिक खिलाड़ी अमित कुमार ने वेस्ट जोन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त किया.

इसके साथ ही नारायणपुर जिले में राज्य शासन मलखम्ब अकादमी खोलने जा रहा है. नारायणपुर क्षेत्र के मलखम्ब खिलाड़ियों ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक अर्जित किया है तथा नेशनल प्रतियोगिता हेतु चयनित भी हो चुके हैं.

अच्छी खेल अधोसंरचनाओं के साथ अच्छे प्रशिक्षक भी

खिलाड़ियों की प्रतिभा को तराशने के अकादमियों में अच्छी खेल अधोसंरचनाओं के साथ-साथ अच्छे प्रशिक्षकों की तैनाती भी की गई है. बिलासपुर अकादमी / एक्सिलेंस सेंटर में वर्तमान में हाईफरफार्मेन्स मैनेजर, हेड कोच एथलेटिक, हेड कोच आरचरी, फिजियो, स्ट्रैन्थ कंडीशनिंग एक्सपर्ट, यंग प्रोफेशनल एवं विभागीय हॉकी के वरिष्ठ प्रशिक्षक (एन.आई.एस) एवं प्रशिक्षक पदस्थ हैं. रायपुर में फुटबॉल के लिए वरिष्ठ प्रशिक्षक (एन.आई.एस) एवं तीरंदाजी एवं एथलेटिक के लिए 01-01 प्रशिक्षक (एन. आई.एस) अपनी सेवा दे रहे हैं . हेड कोच हॉकी की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, शीघ्र ही हेड कोच हॉकी की सेवाएं बिलासपुर अकादमी को प्राप्त होने लगेगी.

रायपुर तीरंदाजी अकादमी के खिलाड़ी शुभम दास ने ऑल इंडिया यूनिवर्सटी तीरंदाजी प्रतियोगिता में दो स्वर्ण पदक प्राप्त किया गया है.

खिलाड़ियों को डाइट मनी सहित अधिकतम सुविधाए

वर्ष 2022-23 के लिए अक्टूबर-2022 में सभी डे-बोर्डिंग के खिलाड़ियों के लिए डाइट मनी के तौर पर 2 लाख 26 हजार 750 रुपए को जारी किए गए हैं. शिवतराई उपकेन्द्र के खिलाड़ियों को 2 लाख 57 हजार रुपए की डाइट मनी प्रदान की गई है.

खेलों के विकास में उद्योगों से भी सहयोग

वर्ष 2019 के बाद से राज्य शासन द्वारा खेल-विभाग के माध्यम से खेल अकादमियों की स्थापना, अधोसंरचना तथा बेहतर सुविधाओं के विकास के लिए लगातार कदम उठाए गए हैं. छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण के अंतर्गत राज्य में उद्योग समूहों के माध्यम से भी कई खेल अकादमियां शुरू की जा रही हैं.
जिंदल उद्योग समूह द्वारा रायपुर में शूटिंग अकादमी, बीएसपी द्वारा नारायणपुर में मलखम्ब अकादमी, गोपाल स्पंज एवं फिल इस्पात द्वारा बिलासपुर कबड्डी अकादमी तथा कोरबा में फुटबॉल, तैराकी, बास्केटबॉल, वालीबॉल की अकादमी का बालको के सहयोग से संचालन किया जाएगा. राज्य शासन द्वारा खेल अकादमियों में शैक्षणिक व्यय, भोजन, आवास, खेल परिधान, आधुनिक प्रशिक्षण, बीमा, डाइट आदि की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं.

जब मिलने लगे ये साइन तो समझ लें LIVE-IN RELATIONSHIP में रहना है खतरनाक

दिल्ली के निक्की यादव मर्डर केस में अब बड़े खुलासे हो रहे हैं. आपसी बहस के बाद निक्की के लिव इन पार्टनर साहिल गहलोत ने मोबाइल चार्जर की केबल (तार) से निक्की का गला घोंट कर हत्या कर दी और शव को काटकर फ्रिज में छिपा दिया. आरोपी 5 दिन के रिमांड पर है. पूछताछ जारी है. निक्की यादव मर्डर के बाद लिव-इन रिलेशनशिप एक बार फिर चर्चा में है.

निक्की और साहिल दोनों लिव-इन में रहते थे. दोनों शादी की बात पर एक दूसरे से झगड़ते रहते थे. साहिल के ऊपर आरोप है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड निक्की का मर्डर किया है. लिवइन में रहना आजकल इतना खतरनाक हो गया है कि इसके परिणाम हत्या के तौर पर सामने आ रहे हैं. लिव इन रिलेशनशिप पूरी तरह से दो लोगों की आपसी सहमति पर आधारित होता है लेकिन सहमति को असमति बनते देर नहीं लगती है. आज हम आपको कुछ ऐसे साइन बताने जा रहे हैं जिससे आपको ये पता चल जाए कि आपको इस रिलेशनशिप से बाहर निकल जाना चाहिए.

पार्टनर आपसे झूठ बोलने लगे

अगर आपने अपने पार्टनर के साथ लिव इन में लंबा समय गुजार लिया है और अब आपको अपने पार्टनर का नेचर कुछ बदला हुआ सा लग रहा है. मसलन बात-बात पर झूठ बोलना, बिना वजह लड़ना तो समझ जाएं आपका पार्टनर अब आपमें इंटरस्टेड नहीं रह गया है. आपको समझना होगा कि आप किसी ऐसे इंसान पर शादी का दवाब नहीं बना सकतीं जो आपसे प्यार ही नहीं करता.

जब आपको कंट्रोल करने लगे पार्टनर

क्या आपका पार्टनर हर बार होने वाले झगड़े की वजह आपको मानता है? क्या वह आपको कंट्रोल करता है? अगर हां तो आपका रिश्ता जहरीला हो चुका है. और समय रहते आपको इस रिश्ते से खुद को अलग कर लेना चाहिए.

जब पार्टनर आपकी हर बात पर चिढ़ने लगे

शुरुआत में जब हम किसी के साथ रिश्ते में जुड़ते हैं तो उसकी बुराइयों में भी अच्छाई ढूढ़ने की कोशिश करने लगते हैं. कोई भी इंसान रिश्ते में प्यार, सम्मान, और बराबरी चाहता है. लेकिन जब आपका पार्टनर आपकी हर बात पर चिढ़ने लगे तो समझ लीजिए ये रिश्ता एकदम जहरीला बन चुका है.

शादी की बात पर आनाकानी करे

जब आप रिश्ते में आए थे उस वक्त आपने अपने पार्टनर के साथ शादी के सपने देखे थे लेकिन अब शादी की बात पर आपका पार्टनर चिढ़ने लगा है तो समझ लीजिए वो शादी या दूसरी जिम्मेदारी से बचना चाहता है. आप इस रिश्ते से तुरंत बाहर आ जाएं क्योंकि शादी की बात कब हत्या तक पहुंच जाती है पता नहीं चलता. आप रिश्ते से बाहर आने के लिए यह सोचें कि इससे बाहर निकलने के बाद जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है.

जब मारपीट पर आने लगे बात

अगर आपका पार्टनर आप पर छोटी-छोटी बातों पर हाथ उठाता हो, और सम्मान नहीं करता है, तो आप एक टॉक्सिक लिव इन रिलेशनशिप में हैं. पार्टनर के हाथ से मार खाने से बेहतर है आप अपने लिए नई जिंदगी तलाश करें. खुद से प्यार करना सीखें और अपने आत्म सम्मान से किसी भी हालत में समझौता न करें. अगर कोई लड़की लिव-इन रिलेशन में रह रही है और उसका बायफ्रेंड उसके साथ मारपीट करता है तो वो पुलिस में FIR दर्ज करा सकती है.

प्रसूति सहायता राशि को 10 हजार से बढ़ाकर 20 हजार रूपए किए जाने का अनुमोदन

- मंत्री डॉ. डहरिया की अध्यक्षता में असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल की बैठक सम्पन्न
- असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को श्रम विभाग की योजनाओं से लाभांवित करें - श्रम मंत्री डॉ. डहरिया
- असंगठित कर्मकार मंडल की योजनाएं मुख्यमंत्री मितान योजना से जुड़ेगी

रायपुर. श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल की बैठक में प्रसूति सहायता की राशि दस हजार रूपये बढ़कार बीस हजार रूपये करने तथा मंडल के कार्या के संपादन हेतु विभागीय पोर्टल और मोबाइल ऐप तैयार करने का निर्णय लिया गया. बैठक में मंडल द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की गहन समीक्षा की गई.

मंत्री डॉ. डहरिया ने श्रम विभाग के अधिकारियों को असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मकारों को राज्य शासन की योजनाओं का फायदा दिलाने के लिए कार्ययोजना तैयार कर कार्य करने के निर्देश दिये हैं. उन्होंने असंगठित क्षेत्र में विभिन्न परम्परागत काम करने वाले कर्मकारों का पंजीयन कर उनकी सूची तैयार करने के निर्देश दिए. बैठक में मंडल की योजनाओं को यथाशीघ्र मुख्यमंत्री मितान योजना जोड़ने का भी निर्णय लिया गया, ताकि कर्मकारों घर पहुंच मंडल की योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ मिलने लगे. मुख्यमंत्री मितान योजना के अंतर्गत सेवाओं में असंगठित कर्मकारों का पंजीयन, मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता, प्रसूति सहायता, छात्रवृत्ति, कौशल उन्नयन, विशेष कोचिंग, चिकित्सा सहायता, पुत्री सायकल सहायता, सफाई कर्मकार प्रसूति, आवश्यक उपकरण सहायता, गंभीर बीमारी चिकित्सा सहायता सहित असंगठित कर्मकारों के लिए संचालित योजनाएं शामिल होंगी. बैठक में विधायक विधायक अनूप नाग और श्रीमती संगीता सिन्हा भी शामिल हुई.

बैठक में श्रम विभाग के सचिव अमृत खलखो ने छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी. अधिकारियों ने बताया कि बैठक में असंगठित कर्मकार मृत्यु दिव्यांग सहायता योजना में आवश्यक संशोधन कर श्रमिकों को फायदा पहुंचाया जायेगा. असंगठित कर्मकारों के प्रवर्ग में धोबी, दरर्जी, माली, मोची, नाई, बुनकर, रिक्शाचालक, घरेलू कामगार और कचरा बिनने वालों को शामिल किया गया है. फुटकर फल, सब्जी विक्रेता, चाय, चाट ठेला लगाने वाले व्यापारी, हमाल, कुली-रेजा, जनरेटर लाईट उठाने वाले और केटरिंग में काम करने वाले, फेरी लगाने वाले कर्मकारों को शामिल किया गया है.

इसी तरह से मोटर साइकल मरम्मत करने वाले, गैरेज मजदूर, परिवहन में लगे मजदूर, आटो चालक, सफाई कामगार, ढोल बाजा बजाने वाले, टेंट हाउस में काम करने वाले, वनोपज में लागे मजदूर, मछुआरा, दाई का काम करने वाले, तांगा बैलगाडी चलाने वाले, तेल पेरने वाले, आगरबती बनाने वाले, घरेलू उद्योग में लगने वाले और खेती हर मजदूर सहित विभिन्न असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के अंतर्गत कुल 56 प्रवर्ग कर्मकारों को अधिसूचित किया गया है. बैठक में छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अंतर्गत संचालित योजनाओं की भी समीक्षा की गई.

बैठक में कर्मकार मंडल के सदस्य जगदीश वर्मा, रामशंकर साहू, आनंद गिल्हरे, शीतलदास मंहत, सर्वजीत सिंह, योगेश चटर्जी, विरेन्द्र चौहान अन्य सदस्य और वित्त, स्वास्थ्य, उद्योग, नगरीय प्रशासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास सहित अन्य विभागों के सदस्य शामिल हुये.

स्वामी आत्मानंद स्कूलः एजुकेशन फ्रेंडली माहौल में बच्चों को मिल रहा निखरने का मौका

आर्थिक अभाव नहीं बन रही बाधा, मिल रही बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा

छत्तीसगढ़ के स्कूली बच्चों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई के लिए बेहतर माहौल बन रहा है. राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई अंग्रेजी स्कूलों की श्रृंखला से जिला मुख्यालयों और विकासखंड स्तर पर बड़ी संख्या में गरीब और कमजोर वर्ग के प्रतिभावान बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं. बहुत ही कम समय में इन स्कूलों में लोकप्रियता हासिल कर ली है. राज्य सरकार द्वारा अंग्रेजी माध्यम के साथ-साथ हिन्दी माध्यम के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल प्रारंभ किए जा रहे हैं. इन स्कूलों में विश्व स्तरीय सुविधाएं मौजूद हैं.

छत्तीसगढ़ के स्कूली बच्चों में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई

प्रदेश में 247 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल और हिंदी माध्यम के 32 स्कूल संचालित हैं, वहीं आगामी शिक्षण सत्र से 422 स्कूलों का संचालन किया जाना भी प्रस्तावित है. नये प्रस्तावित स्कूलों में सरगुजा और बस्तर संभाग के 252 स्कूल शामिल होंगे, ताकि सुदूर अंचलों एवं पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले बच्चे भी अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई कर सके. अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की सफलता को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा आगामी शैक्षणिक सत्र से अंग्रेजी माध्यम कॉलेज प्रारंभ करने का भी निर्णय लिया गया है.

हिन्दी माध्यम स्कूलों में सीबीएससी का पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है

स्वामी आत्मानंद स्कूलों की लोकप्रियता का अंदाजा मुख्यमंत्री के भेंट-मुलाकात कार्यक्रमों के दौरान इन स्कूलों की मांग और इन स्कूलों में पढ़ने वाले फर्राटेदार अंग्रेजी से लगाया जा सकता है. इन स्कूलों के प्रारंभ होने से गरीब और कमजोर तबके के प्रतिभावान बच्चों के पालकों को निजी स्कूलों की महंगी फीस से काफी राहत मिली है. इन स्कूलों में नाममात्र की फीस पर अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा के साथ-साथ् विश्व स्तरीय सुविधाएं, बेहतर शैक्षणिक माहौल मिल रहा है.

विभिन्न खेलों की सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी है।

राज्य सरकार द्वारा इन स्कूलों को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ के प्रतिभावान छात्रों को अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है ताकि वे प्रतियोगी परीक्षाओं में अन्य राज्यों के विद्यार्थियों से पीछे न रहे. सभी अंगेजी माध्यम और हिन्दी माध्यम स्कूलों में सीबीएससी का पाठचक्रम संचालित किया जा रहा है.गौरतलब है कि 03 जुलाई 2020 को प्रदेश में स्वामी आत्मानंद स्कूल की सबसे पहले शुरूआत हुई थी. योजना के अंतर्गत प्रांरभ हुए 247 स्कूलों में लगभग ढ़ाई लाख बच्चे अध्ययनरत हैं. इन स्कूलों में अत्याधुनिक लाइब्रेरी, लैंग्वेज लैब, कम्प्यूटर और साइंस लैब के साथ ही टेनिस और बैडमिंटन सहित विभिन्न खेलों की सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी है.

विशेष लेख -
दानेश्वरी संभाकर
सहायक संचालक, रायपुर

अडानी को 11 लाख करोड़ का झटका !

रायपुर. दुनिया के सबसे अमीर कारोबारियों में दूसरे नंबर पर पहुंच चुके गौतम अडानी को एक महीने में 11 लाख करोड़ रुपये का झटका लगा है. 24 जनवरी के बाद से गौतम अडानी ग्रुप की कंपनियों के मार्केट कैप में 11 लाख करोड़ रुपए की कमी आई है. अरबपति बिजनेसमैन गौतम अडानी ग्रुप की कंपनियों की मार्केट वैल्यू 1 महीने की अवधि में 57% से ज्यादा गिर गई है. अमेरिकी शार्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की धमाकेदार रिपोर्ट के बाद से गौतम अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में गिरावट जारी है.

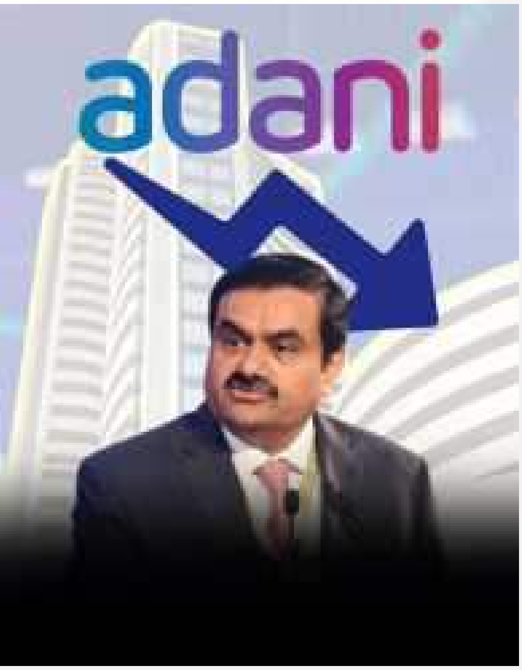

गौतम अडानी ग्रुप की सभी 10 लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप अब 8.2 लाख करोड़ रुपए है. 24 जनवरी को यह 19.2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा था. गौतम अडानी ग्रुप की अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन और अडानी टोटल गैस में मंगलवार को 5% का लोअर सर्किट लगा है, जबकि अडानी पावर 5% की रफ्तार से काम कर रही है.

एसीसी और अंबुजा सीमेंट के शेयर हिमाचल प्रदेश में एक सीमेंट संयंत्र में परिचालन शुरू होने की खबरों से मामूली रूप से अधिक हैं. अडानी एंटरप्राइजेज के शेयर अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर से 61% की हानि पर कारोबार कर रहे हैं जबकि अदानी पोर्ट्स के शेयर अपने उच्च स्तर से 40% की हानि पर कारोबार कर रहे हैं.

अगर शेयरों के भाव के हिसाब से बात करें तो अहमदाबाद के 60 साल के इस कारोबारी ने निवेशकों को लुभाने की पूरी कोशिश की और खूब कोशिश की, लेकिन निवेशकों पर इसका कोई असर होता नजर नहीं आ रहा है. निवेशकों को आश्वस्त करने की कोशिश में, अडानी पोर्ट्स ने कल हीठप्प्यूचुअल फंड को रू.1500 करोड़ दिए हैं. मार्च में अडानी पोर्ट कमर्शियल पेपर के बदले एसबीआई म्यूचुअल फंड को 1000 करोड़ रुपए और देने की तैयारी कर रहा है.

गौतम अडानी की कंपनियां चालू वित्त वर्ष में 5000 करोड़ रुपये का कर्ज पहले ही चुका चुकी हैं. गौतम अडानी ग्रुप को ब्रिज लोन के रूप में 50 करोड़ डॉलर का कर्ज अगले महीने चुकाना है. वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने हाल ही में अडाणी समूह की चार कंपनियों का आउटलुक घटाया है. हालांकि अडानी पोर्ट्स की रेटिंग और आउटलुक में कोई कमी नहीं की गई.

छत पर की ड्रैगन फ्रूट गार्डनिंग की शुरुआत अब जॉब के साथ इसकी खेती कर रहा है इंजीनियर

साल 2020 कोरोना महामारी के कारण सभी के लिए पर्सनल और प्रोफेशनल, दोनों तरह से चुनौतीपूर्ण रहा है. लेकिन तमाम परेशानियों के बावजूद कुछ उद्यमियों ने अलग-अलग तरह के इनोवेशन के साथ आगे का रास्ता बनाया. इसी संकट के समय में राजम के इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने वर्क फ्रॉम होम करते हुए एक और पहल की.

अपनी सॉफ्टवेयर जॉब के अलावा, उन्होंने अपनी छत को ड्रैगन फ्रूट फार्म में बदल दिया. अपने निरंतर प्रयासों और समर्पण के माध्यम से, वह अब अन्य सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के लिए प्रेरणा बन गए हैं.

नौकरी के साथ-साथ शुरू की गार्डनिंग

राजम कस्बे के दोलापेटा के सुदर्शनम अधिकारी (40) बेंगलुरु में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम कर रहे हैं. वह कोविड-19 लॉकडाउन के कारण वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं. इसी दौरान, उन्हें ड्रैगन फ्रूट लगाने का विचार आया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुदर्शनम अधिकारी ने कहा कि उन्हें अपने माता-पिता से गार्डनिंग का पैशन मिला है.

उनके बचपन से ही वे अपने घर में बागवानी करते आ रहे हैं. अपनी मां की सलाह पर उन्होंने अपने घर की छत पर जैविक खेती पद्धति से ड्रैगन फ्रूट की खेती करने का फैसला किया क्योंकि इसमें पानी की खपत कम होती है और बाजार में इसकी अच्छी मांग है. उन्होंने छह सेंट की छत की जगह को एक खेत की तरह तैयार किया और 2021 की गर्मियों में 100 से अधिक ड्रैगन फ्रूट लगाए.

150 किलोग्राम ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन

आठ महीने के बाद, उन्होंने अपनी पहली फसल के रूप में लगभग 150 किलोग्राम ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन किया. उन्होंने अपनी पहली फसल में लगभग 1.5 लाख रुपये का निवेश किया, लेकिन रिटर्न के रूप में उन्हें 50,000 रुपये मिले. इस साल उन्होंने आधा एकड़ खेत में खेती की है और अगले कुछ महीनों में दूसरी फसल की उम्मीद कर रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाजार में ड्रैगन फ्रूट की भारी मांग है. यह फल किसानों के लिए एक आकर्षक फसल है. अगर सब कुछ ठीक रहा, तो यह फसल अगले 20 वर्षों तक अच्छा रिटर्न दे सकती है.

गौमूत्र से बने जैविक कीटनाशक

ब्रम्हास्त्र और फसल वृद्धिवर्धक जीवामृत से बढ़ा उत्पादन, ग्रामीणों को हुई 25.74 लाख रुपये की आय

रायपुर. राज्य में गौमूत्र से जैविक कीटनाशक ब्रम्हास्त्र और फसल वृद्धिवर्धक जीवामृत का उत्पादन और उपयोग खेती में होने लगा है. गौठानों में 4 रुपये लीटर की दर से अब तक 1 लाख 26 हजार 858 लीटर गौमूत्र क्रय किया जा चुका है, जिससे गौठानों में महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा 47 हजार 447 लीटर कीट नियंत्रक ब्रम्हास्त्र और 21 हजार लीटर वृद्धिवर्धक जीवामृत बनाया गया है. खेती में उपयोग के लिए किसानों द्वारा अब तक 59 हजार 557 लीटर ब्रम्हास्त्र और जीवामृत क्रय किया गया है, जिससे गौठानों को 25 लाख 74 हजार 355 रुपये की आय हुई है.

गोबर से 27.56 लाख क्विंटल कम्पोस्ट खाद का उत्पादन

गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गौठानों में 2 रुपये किलों में गोबर की खरीदी गौठानों में महिला समूहों द्वारा अब तक कुल 27 लाख 56 हजार क्विंटल से ज्यादा कम्पोस्ट का उत्पादन किया गया है. जिसमें 22 लाख 5 हजार 138 किवंटल वर्मी कम्पोस्ट, 5 लाख 50 हजार 862 क्विंटल से ज्यादा सुपर कम्पोस्ट और 18,924 क्विंटल सुपर कम्पोस्ट प्लस खाद शामिल है, जिसे सोसायटियों के माध्यम से क्रमशः 10 रुपये, 6 रुपये और 6.50 रुपये प्रतिकिलो की दर पर विक्रय किया जा रहा है. महिला समूह गोबर से खाद के अलावा गो-कास्ट, दीया, अगरबत्ती, मूर्तियां और अन्य सामग्री का निर्माण और विक्रय कर लाभ अर्जित कर रही हैं. गौठानों में महिला समूहों द्वारा इसके अलावा सब्जी और मशरूम का उत्पादन, मुर्गी, बकरी, मछली पालन और पशुपालन के साथ-साथ अन्य आय मूलक विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है, जिससे महिला समूहों को अब तक 105 करोड़ 67 लाख रुपये की आय हो चुकी है.

राज्य में गौठानों से 11,885 महिला स्व-सहायता समूह सीधे जुड़े हैं, जिनकी सदस्य संख्या 1,36,123 है. गौठानों में क्रय गोबर से विद्युत और प्राकृतिक पेंट सहित अन्य सामग्री का भी उत्पादन किया जा रहा है. 3 लाख 23 हजार से अधिक ग्रामीण लाभान्वित- राज्य में गोधन के संरक्षण और संर्वधन के लिए गांवों में गौठानों का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है. गौठानों में पशुधन देख-रेख, उपचार एवं चारे-पानी का निःशुल्क प्रबंध है. राज्य में अब तक 10,743 गांवों में गौठानों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिसमें से 9671गौठान निर्मित और शेष गौठान निर्माणाधीन है. गोधन न्याय योजना से 3 लाख 23 हजार 983 ग्रामीण, पशुपालक किसान लाभान्वित हो रहे हैं.

गौठानों में 17.58 लाख क्विंटल धान पैरा एकत्र

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अपील पर राज्य के किसानों द्वारा अपने गांवों के गौठानों को पैरादान किए जाने का सिलसिला लगातार जारी है. राज्य के किसान भाई पैरा को खेतों में जलाने के बजाय उसे गौमाता के चारे के प्रबंध के लिए गौठान समितियों को दे रहे हैं. ऐसे किसान भाई जिनके पास पैरा परिवहन के लिए ट्रेक्टर या अन्य साधन उपलब्ध है, वह स्वयं धान कटाई के बाद पैरा गौठानों में पहुंचाकर इस पुनीत कार्य में सहभागिता निभा रहे हैं. गौठान समितियों द्वारा भी किसानों से दान में मिले पैरा का एकत्रीकरण कराकर गौठानों में लाया जा रहा है. गौठानों में अब तक 17 लाख 58 हजार क्विंटल पैरा गौमाता के चारे के लिए उपलब्ध है.

रायपुर. रोजगार, स्व-रोजगार, स्थानीय संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और उद्यमिता विकास को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किये हैं. इन चार वर्षों में ग्रामीण तबकों और सुदूर वनांचल क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचा है, जिसके परिणाम स्वरुप प्रदेश के बनवासी, ग्रामीण, किसान, मजदूर और कारीगर वर्ग को बड़ा लाभ हुआ है. छत्तीसगढ़ सरकार के जनहितैषी नीतियों का ही परिणाम है कि आज प्रदेश का हर वर्ग आर्थिक रूप से सशक्त और सम्पन्न हो रहा है. छत्तीसगढ़ के वनांचल क्षेत्रों में निवास करने वाले वनवासी और आदिवासियों के हित में और वनों में उनके अधिकारों को और अधिक दृढ करने और वनोपज से आय में वृद्धि के सपने को साकार करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं.

वन संपदाओं से समृद्ध हो रहे प्रदेश के संग्राहक, 4 सालों में वनोपजों की खरीदी में हुई 78 गुना से ज्यादा की वृद्धि

राज्य में पहली बार समर्थन मूल्य पर कोदो, कुटकी, रागी की खरीदी की गई. लघु धान्य फसलों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में मिलेट मिशन भी चलाया जा रहा है. छत्तीसगढ़ में देश का 74 प्रतिशत लघु वनोपज संग्रहित होता है. सरकार ने संग्राहकों के हित में लघु वनोपजों की संख्या में 9 गुना वृद्धि करते हुए 7 से बढ़ाकर 65 लघु वनोपजों की खरीदी करने का निर्णय लिया यही कारण है कि इन चार सालों में संग्राहकों की संख्या में भी 4 गुना से ज्यादा की बढ़ोत्तरी हुई है, वर्ष 2018-19 में संग्राहकों की संख्या 1.5 लाख थी जो आज बढ़कर 6 लाख हो गई है. लघु वनोपजों की खरीदी की मात्रा में भी 78 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है, वर्ष 2021-22 में कुल 42 हजार मीट्रिक टन लघु वनोपजों की खरीदी की गई है, जबकि यह मात्रा वर्ष 2018-19 में 540 मीट्रिक टन थी.

छत्तीसगढ़ सरकार ने अन्य राज्यों की तुलना में पेसा कानून को लेकर बेतहतर प्रावधान बनाए हैं ताकि वनांचलों में स्थानीय स्वशासन सशक्त हो सकें और वन में रहने वाले लोगों को ज्यादा अधिकार मिल सकें. सरकार आदिवासियों के रोजगार, स्व-रोजगार के लिए और उनकी आय में वृद्धि हो सकें इस दिशा में अनेकों प्रयास कर रही है.

छत्तीसगढ़ पूरे देश का सबसे बड़ा वनोपज संग्राहक राज्य है, इस वर्ष राज्य सरकार ने 120 करोड़ रुपये का भुगतान वनोपज संग्राहकों को किया है. वर्ष 2020-21 में 153.46 करोड़ रुपये का लघु वनोपज देशभर में खर्च की गई राशि का अकेला 78 प्रतिशत है. पिछले चार वर्षों में छत्तीसगढ़ सरकार की जनहितैषी योजनाओं के परिणाम स्वरूप 13 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों और 06 लाख वनोपज संग्राहकों को 250 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सालाना आय हुई है. संग्रहण के साथ-साथ 129 वनधन विकास केन्द्रों के माध्यम से वनोपजों का प्रसंस्करण कर 134 हर्बल उत्पादों का छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड के नाम से विक्रय करने के लिए मुख्यमंत्री की पहल पर 6 सी-मार्ट और 30 संजीवनी केन्द्रों की स्थापना की गई है.

संग्राहको के हित में तेन्दूपत्ता संग्रहण दर 25 सौ रुपये से बढ़ाकर 4 हजार रुपये प्रति मानक बोरा किया गया है, वहीं संग्राहको को 4 वर्ष में 2146.75 करोड़ रुपये तेन्दूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक और 339.27 करोड़ रुपये प्रोत्साहन पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है. संग्राहक परिवारों के हित में शहीद महेन्द्र कर्मा तेन्दूपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत अब तक 4692 हितग्राहियों को 71.02 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गई है. वन अधिकारों के क्रियान्वयन में भी छत्तीसगढ़ देश में अग्रणी राज्य है. छत्तीसगढ़ सरकार ने लाख उत्पादन को कृषि का दर्जा दिया है और लाख उत्पादक कृषकों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करने की योजना भी लागू की है, जिसके प्रभाव स्वरूप आज लाख उत्पादक किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं.

आ गया WhatsApp का लेटेस्ट अपडेट,
अब एक बार में भेज पाएंगे 30 से ज्यादा Photos और Videos

पहले यूजर्स के पास केवल फोटो और वीडियो में ही कैप्शन लिखने का ऑप्शन था. व्हाट्सएप ने एक नया फीचर भी लॉन्च किया है.

रायपुर. व्हाट्सएप पर 30 से ज्यादा फोटो नहीं भेज पाने की वजह से आप थक गए हैं? जल्द ही मैसेजिंग ऐप WhatsApp पर आप 100 से ज्यादा तस्वीरें और वीडियो भेज पाएंगे. पहले एक बार में ज्यादा से ज्यादा 30 फोटो और वीडियो भेजे जा सकते थे. हालांकि, व्हाट्सएप ने अब एंड्राइड यूजर्स के लिए अपडेट वर्जन लॉन्च कर दिया है. एंड्राइड वर्जन 2.22.24.73 के लिए लिमिट 30 से बढ़ाकर 100 कर दी है.

फोटो और वीडियोज की लिमिट बढ़ाने के अलावा व्हाट्सएप ने एक नया फीचर भी लॉन्च किया है. जिसमें यूजर्स डॉक्यूमेंट्स में कैप्शन लिख पाएंगे.वॉट्सऐप आईओएस फोन्स पर भी एक बार में 100 फोटो ट्रांसफर करने के फीचर की टेस्टिंग कर रहा है.

व्हाट्सएप लाया और भी अपडेट

पहले यूजर्स के पास केवल फोटो और वीडियो में ही कैप्शन लिखने का ऑप्शन था, लेकिन अब वे पर्सनल और ग्रुप चैट में शेयर किए गए डॉक्यूमेंट्स में भी कैप्शन एड कर सकते हैं. व्हाट्सऐप ने ग्रुप सब्जेक्ट्स और डिस्क्रिप्शन के लिए कैरेक्टर लिमिट भी बढ़ा दी है ताकि यूजर्स को अपने ग्रुप्स को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिल सके.

Android यूजर्स के लिए है अपडेट

लेटेस्ट अपडेट फिलहाल Android यूजर्स के लिए ही उपलब्ध हैं, कंपनी जल्द ही उन्हें iOS के लिए भी लॉन्च कर सकती है. व्हाट्सएप बिजनेस यूजर्स के लिए "Kept Messages" नाम के एक फीचर की टेस्टिंग भी जारी है. यह सुविधा यूजर्स को गायब होने वाले मैसेजेस को रखने की अनुमति देगी. व्हाट्सएप आईओएस पर ट्रांसक्रिप्शन की भी टेस्टिंग कर रहा है. इसके अलावा पिछले साल व्हाट्सएप ने फाइल लिमिट को 100MB से बढ़ाकर 2GB कर दिया था, लेकिन यह सुविधा अभी तक iOS यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं है.

मीडिया शेयर करना यूजर्स के लिए हुआ आसान

इन नए फीचर्स के इस्तेमाल के बाद यूजर्स के लिए WhatsApp पर मीडिया और डॉक्यूमेंट्स शेयर करना आसान हो जाएगा. फोटो और वीडियो की लिमिट बढ़ जाने से यूजर्स अब एक मैसे में ज्यादा कंटेंट शेयर कर सकेंगे. डॉक्यूमेंट्स पर कैप्शन की नई सुविधा यूजर्स के लिए उनके द्वारा साझा की जाने वाली फाइलों में मैसेज समझना आसान हो जाएगा.

सोनू सूद ने लॉन्च की भारत की सबसे बड़ी थाली, 8 फीट लंबी थाली में खा सकते हैं 20 लोग

एक्टर सोनू सूद का आज हर कोई फैन है. उन्होंने जिस तरह कोरोना महामारी में लोगों की मदद की, उसके लिए आज भी लोग उन्हें सम्मानित करते हैं.

सैंड आर्टिस्ट से लेकर पेंटर तक कई लोगों ने सोनू सूद का सम्मान किया है

सोनू सूद ने किया "इंडियाज बिगेस्ट प्लेट" का उद्घाटन

मुंबई. महामारी के दौरान बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने बहुत से लोगों की मदद की. वह अक्सर अपनी मानवता के कारण सुर्खियां बटोरते हैं. कोविड के दौरान, देश भर के नेटिजन्स ने मजदूरों, बेघरों, भूखे और बुजुर्गों की मदद करने के लिए उनकी प्रशंसा की.

सैंड आर्टिस्ट से लेकर पेंटर तक कई लोगों ने सोनू सूद का सम्मान किया है और जरूरतमंदों और वंचितों की मदद करने के लिए उनकी तारीफ की है. वह अब अपने फैन्स के लिए नए बिजनेस आउटलेट का उद्घाटन करते नजर आते हैं.

किया "इंडियाज बिगेस्ट प्लेट" का उद्घाटन

हाल ही में, अभिनेता हैदराबाद के जिस्मत जेल मंडी रेस्तरां में मौजूद थे और उन्होंने तस्वीरें खिंचवाईं. एक बार में 20 लोगों को परोसने वाली थाली का नाम अभिनेता के नाम पर रखा गया है. सूद ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया कि इंडियाज बिगेस्ट प्लेटष् का नाम अब उनके नाम पर रखा गया है.

अभिनेता के पोस्ट से पता चलता है कि वह इस बात से बहुत खुश हैं कि वह दुनिया की सबसे बड़ी नॉन-वेज प्लेट लॉन्च करने में सक्षम हैं. उनके नाम की थाली कथित तौर पर 20 लोगों को परोसती है और 8 फीट लंबी है.

रेस्तरां ने की तारीफ

रेस्टोरेंट ने इंस्टाग्राम पर फोटो पोस्ट करते हुए कैप्शन में लिखा, श्सर आपके पास सबसे बड़ा दिल है और हमें थाली के लिए इससे बेहतर नाम नहीं मिल सकता है सर. हैदराबाद में आपसे मिलकर वास्तव में विनम्र और खुश हैं और आपकी उपस्थिति अभी भी यहां है, जिस्मत जेल मंडी में उस पॉजिटिविटी को बनाने के लिए धन्यवाद. इस आयोजन और थाली को व्यापक रूप से सफल बनाने के लिए हमारे ग्राहकों को धन्यवाद."

भूपेश सरकार की योजनाओं से

ग्रामीण महिलाओं के सपनों को लगे पंख, घर की चार दिवारी से निकलकर पूरे कर रही अरमान

वर्मी कंपोस्ट से हुई 36 लाख की आय

रायपुर. छत्तीसगढ़ में गोबर से लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है. गोबर से वर्मी कम्पोस्ट के साथ-साथ पेंट और बिजली भी तैयार किया जा रहा है. गांवों में महिला समूह की कोई सदस्य टू-व्हीलर खरीद रही है, तो कई ने गहने भी खरीदे. किसी ने अपने परिवार के सदस्य के लिए शादी के लिए कर्जा चुकाया है. ये सभी महिलाएं गरीब परिवारों से ताल्लुक रखती हैं. जिन्होंने कभी चार दीवारी से बाहर कदम नहीं रखा था. ऐसे समूहों में आत्मविश्वास और काम के प्रति ललक को देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार गोबर से बने उत्पादों को प्रोत्साहित कर रही है.

मनेन्द्रगढ़ शहरी क्षेत्र की महिलाओं ने वर्ष 2020 में गौठानों से जुड़कर वर्मी कंपोस्ट तैयार करने का काम शुरू किया. इन महिलाओं के द्वारा बनाए गए स्वच्छ मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र स्तरीय संघ ने पिछले तीन साल में एक करोड़ रुपये का वर्मी कंपोस्ट तैयार कर बेचा है. ये आंकड़ा राज्य के बाहर के लोगों के लिए चौकाने वाला हो सकता है लेकिन छत्तीसगढ़ में कोई नई बात नहीं है. यहां बड़ी संख्या में महिलाएं गौठानों से जुड़कर गोबर से वर्मी कम्पोस्ट तैयार कर अच्छी आमदनी प्राप्त कर रही हैं.

महिलाओं द्वारा तैयार वर्मी कम्पोस्ट की बिक्री सहकारी समितियों के माध्यम से की जा रही है.

स्वच्छ मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र स्तरीय संघ ने वर्ष 2020 में गोधन न्याय योजना के शुभारंभ के साथ ही शहरी गौठान में गोबर खरीदी का कार्य शुरू किया. अब तक यहां से 33 हजार 195 क्विंटल गोबर क्रय किया गया, जिससे 10 हजार 809 क्विंटल वर्मी खाद बनाया जा चुका है और 10 हजार 32 क्विंटल वर्मी बेचा गया है. इससे उन्हें 1 करोड़ रुपये से ज्यादा की आय हुई. महिला संघ को पिछले तीन साल में अब तक 36 लाख रुपये से अधिक का लाभांश प्राप्त हुआ है. इन्हें पूर्व से डोर टू डोर कचरा एकत्र के लिए करीब 6 हजार रुपरये महीना दिया जा रहा था. अब उन्हें वर्मी कम्पोस्ट के विक्रय के लाभांश से अतिरिक्त आय भी हो रही हैं. अपनी आय में वृद्धि से महिला समूह की सदस्य उत्साहित है.

स्वच्छ मनेन्द्रगढ़ क्षेत्र स्तरीय संघ की अध्यक्ष प्रीति टोप्पो बताती है कि उन्हें मिले लाभांश से उसने बहन की शादी में कुछ कर्ज लिया था, वो इस पैसे से छूट गया, बच्चों को स्कूल आने-जाने के लिए साईकल लेकर दी और घर के लिए टीवी भी ले लिया. संघ की सदस्य सविता दास कहती हैं कि जब गोधन न्याय योजना शुरू हुई तो शहर के गौठान में समूह के रूप में जुड़कर वर्मी कम्पोस्ट निर्माण का कार्य शुरू किया. जैसे-जैसे उत्पादन एवं विक्रय से लाभ मिला, लोगों का हमारे प्रति नजरिया बदलने लगा. इस योजना से हमें स्वरोजगार का जरिया मिला है और वर्मी खाद विक्रय से जो लाभांश मुझे मिला उससे मैंने टू व्हीलर गाड़ी खरीदी है.

27 लाख क्विंटल वर्मी खाद का उत्पादन

राज्य में गौठानों में वर्मी कंपोस्ट तैयार करने 11 हजार 477 महिला समूह की लगभग सवा लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी है. इनके द्वारा 27 लाख क्विंटल से अधिक वर्मी कम्पोस्ट तैयार किया गया है. महिला समूहों द्वारा 198 करोड़ रुपये का वर्मी कंपोस्ट बेचा जा चुका है. यही वजह है कि पिछले तीन सालों में छत्तीसगढ़ में खाद की कमी नहीं हुई. वर्मी कम्पोस्ट का किसानों द्वारा भरपूर इस्तेमाल किया. राज्य सरकार के प्रयासों की सफलता का सबूत है कि इस वर्ष छत्तीसगढ़ में धान का बम्पर उत्पादन हुआ है और राज्य में समर्थन मूल्य में 107 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है.

भूलकर भी इस जगह ना रखें मनी प्लांट, बढ़ने लगेगी आर्थिक तंगी

वास्तु शास्त्र में मनी प्लांट का खास महत्व है. आर्थिक स्थित सही करने के लिए वास्तु में मनी प्लांट के कुछ खास नियम बताए गए हैं. जानते हैं इन नियमों के बारे में.

वास्तु शास्त्र में पेड़-पौधों का खास महत्व होता है. वास्तु में मनी प्लांट को भी खास माना गया है. पैसों की तंगी दूर करने और आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए मनी प्लांट का पौधा घर में लगाना शुभ माना जाता है. माना जाता है कि जिस घर में मनी प्लांट होता है वहां मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है. वास्तु शास्त्र के मुताबिक मनी प्लांट का पौधा लगाने के कुछ खास नियम होते हैं. अगर इन वास्तु नियमों का पालन ना किया जाए तो फायदे की बजाए घर में इसके नुकसान देखने को मिलते हैं. मनी प्लांट लगाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. वास्तु में दिशा का विशेष महत्व होता है. मनी प्लांट के पौधे को कभी भी उत्तर-पूर्व दिशा में नहीं लगाना चाहिए. ऐसा करने से घर के सदस्यों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है. मनी प्लांट को हमेशा दक्षिण-पूर्व दिशा में लगाना चाहिए. ये दिशा भगवान गणेश की दिशा मानी जाती है. इस दिशा में मनी प्लांट लगाने से घर में सुख-समृद्धि आती है.

वास्तु के अनुसार मनी प्लांट का पौधा जैसे-जैसे बढ़ता है, व्यक्ति वैसे-वैसे तरक्की करता है. ध्यान रखें कि मनी प्लांट के पौधे की बेल कभी भी जमीन को नहीं छूनी चाहिए. इसकी बेल नीचे आने पर धन हानि होती है. मनी प्लांट को कभी भी सूखने न दें. अगर इसके पत्ते सूखते या पीले हो जाते हैं, तो इसे तुरंत हटा दें. सूखा हुआ मनी प्लांट घर में दुर्भाग्य लेकर आता है.

मनी प्लांट को कभी भी घर के बाहर नहीं लगाना चाहिए. कहा जाता कि किसी बाहरी व्यक्ति की नजर पड़ने पर मनी प्लांट का विकास रुक जाता है. इसका असर घर के सदस्यों की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है. इस पौधे को हमेशा घर के अंदर ही लगाएं.

वास्तु शास्त्र के अनुसार मनी प्लांट का लेन-देन करना अशुभ होता है. ऐसा करने पर शुक्र ग्रह क्रोधित होते हैं और व्यक्ति को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है.

अडानी के शेयरों में गिरावट का असर, एलआईसी ने 50 दिनों में गंवाए 50 हजार करोड

सरकारी बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की गिनती शेयर बाजार के बड़े इन्वेस्टर्स में होती है. भारतीय बाजार में तो एलआईसी सबसे बड़ी घरेलू संस्थागत निवेशक है. कंपनी शेयर बाजार से मोटा मुनाफा भी कमाती रही है और अपने शेयरधारकों व बीमाधारकों के लिए वैल्यू बनाती रही है. हालांकि पिछले कुछ दिन एलआईसी के लिए शेयर बाजार में ठीक नहीं रहे हैं.

इस कारण हुआ नुकसान

शेयर बाजार की अन्य कंपनियों की तरह एलआईसी ने अडानी समूह के शेयरों में भी इन्वेस्ट किया हुआ है. इसके चलते एलआईसी को खासा नुकसान हुआ है, क्योंकि अडानी समूह के शेयर पिछले महीने से भारी बिकवाली का शिकार हो रहे हैं. अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग ने जबसे अडानी समूह को लेकर विवादास्पद रिपोर्ट जारी की है, तब से लगभग हर रोज समूह के सारे शेयर गिर रहे हैं. इसके चलते एलआईसी को सिर्फ बीते 50 दिनों में करीब 50 हजार करोड़ रुपये का घाटा हुआ है.

अडानी के इन शेयरों में निवेश

शेयर बाजार पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, एलआईसी ने अडानी समूह की सात कंपनियों अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनामिक जोन, अडानी टोटल गैस, अडानी ट्रांसमिशन, अंबुजा सीमेंट्सऔर एसीसी के शेयरों में निवेश किया हुआ है.

इस तरह कम हुई वैल्यू

अडानी समूह के इन सात शेयरों में एलआईसी के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 31 दिसंबर 2022 को 82,970 करोड़ रुपये थी. यह वैल्यू कम होकर 23 मार्च 2023 को 33,242 करोड़ रुपये रह गई. इस तरह पिछले करीब 50 दिनों में अडानी के शेयरों में एलआईसी के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में 49,728 करोड़ रुपये की गिरावट आई है. आपको बता दें कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी समूह पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं. 24 जनवरी 2023 को सामने आई रिपोर्ट में समूह के ऊपर अकाउंटिंग में धोखाधड़ी और शेयरों के भाव में हेर-फेर करने जैसे आरोप लगे हैं. हालांकि अडानी समूह ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में लगाए गए सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया.

अडानी के शेयरों में इतनी गिरावट

बहरहाल, अडानी समूह के शेयरों में लगातार गिरावट का दौर जारी है. इस साल की बात करें तो अब तक अडानी टोटल गैस के शेयरों में सबसे ज्यादा करीब 80 फीसदी की गिरावट आई है. इसके बाद अडानी ग्रीन एनर्जी में करीब 74 फीसदी, अडानी ट्रांसमिशन में 71 फीसदी, अडानी एंटरप्राइजेज में 64 फीसदी, अडानी पावर में 48 फीसदी और एनडीटीवी में करीब 42 फीसदी की गिरावट आ चुकी है. इनके अलावा अडानी विल्मर, अंबुजा सीमेंट्स, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनामिक जोन और एसीसी के शेयरों में 28 फीसदी से 40 फीसदी तक की गिरावट आई है. कुल मिलाकर इस साल अडानी समूह के एमकैप में अब तक 12 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की गिरावट आई है.

किसान कर सकते हैं पत्तों की खेती, लाखों की कमाई का आसान तरीका

> रायपुर. आज कई किसान कुछ खास किस्म के पेड़ों के पत्तों की खेती करके काफी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं. खास बात ये हैं कि इनमें से कुछ पत्तों की खेती के लिए सरकार से सब्सिडी भी दी जाती है. ऐसे में किसान इन पत्तों की खेती करके काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं. इन पत्तों की खेती में लागत भी कम आती है और मुनाफा इससे कहीं ज्यादा होता है.

तेंदूपत्ते की खेती

सबसे पहले बात कर लेते हैं देश में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा खेती की जाने वाले पत्ती की. आपको इस बारे में शायद ही जानकारी होगी कि तेंदूपत्ते का इस्तेमाल बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है. अगर आप तेंदूपत्ते का बिजनेस शुरू करते हैं. ऐसे में इस बिजनेस को शुरू करने के बाद अपनी शानदार कमाई कर सकते हैं.

पान के पत्तों की खेती

पान के पत्तों का चयन भारत में काफी पुराना है. सरकार की ओर से किसानों को सब्सिडी का लाभ भी प्रदान किया जाता है. पान की कई प्रकार की वेरायटी आती है जिनमें मगही पान की खेती किसान काफी करते हैं. भारत में दक्षिण और पूर्वी इलाकों में पान की खेती काफी की जाती है. एक अनुमान के मुताबिक बेहतर कृषि तकनीकों का इस्तेमाल करके इसकी खेती से प्रति हैक्टेयर 100 से 125 क्विंटल तक पान के पत्तों की पैदावार प्राप्त की जा सकती है. दूसरे और तीसरे साल इसकी 80 से 120 क्विंटल तक उपज प्राप्त होती है.

तेज पत्ता की खेती

तेज पत्ता का इस्तेमाल मसाले के रूप में होता है. इसके प्रयोग गरम मसाला बनाने में किया जाता है. साथ ही इसे सब्जी, पुलाव आदि बनाने में भी मसाले के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. ये सूखा होने पर ही बेचा जाता है. इसे पत्तों के रूप में बेचा जा सकता है. वहीं इसको पीसकर भी इसे बाजार में सप्लाई किया जा सकता है. तेज पत्ते की खुशबू काफी अश्छी होती है और यही कारण है कि ये इसका इस्तेमाल सब्जी का स्वाद और ज्यादा बढ़ा देता है. आजकल बाजार में तेज पत्ते की डिमांड काफी है. इसे देखते हुए किसान इसके पत्तों की खेती करके बेहतर लाभ प्राप्त कर सकते हैं. इसकी खेती पर भी किसान सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं. तेज पत्ते की खेती के लिए राष्ट्रीय औषधीय बोर्ड की ओर से 30 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाता है. एक अनुमान के मुताबिक तेज पत्ता के एक पौधे से किसान सालाना 5 हजार रुपए की कमाई कर सकते हैं. यदि ऐसे ही 25 पौधे लगा दिए जाए तो साल भर में आसानी से 75 हजार रुपए से लेकर एक लाख रुपए की कमाई तेज पत्ता से की जा सकती है.

सहजन के पत्तों की खेती

सहजन एक ऐसा पौधा है जिसके फल, फूल और पत्तियां सभी का उपयोग किया जाता है. इसके पत्तों का उपयोग आयुर्वेदिक बूटी के रूप में किया जाता है. सरकार की ओर से प्रति हैक्टेयर में सहजन की खेती के लिए 74000 रुपए की लागत तय की गई है. एक अनुमान के मुताबिक यदि किसान एक एकड़ में सहजन के 1200 पौधे लगाते हैं और उन्नत कृषि क्रियाओं का उपयोग करते हैं तो इसकी पत्तियां बेचकर किसान 60 हजार रुपए तक की कमाई कर सकते हैं. इसके अलावा इसकी फलियों को बेचकर किसान एक लाख रुपए की कमाई आसानी से कर सकते हैं.

केले के पत्तों की खेती

केले को बेचकर तो कमाई की जा ही सकती है, लेकिन इसके पत्तों से भी काफी अच्छा पैसा कमाया जा सकता है. इन दिनों लोग प्राकृतिक चीजों के इस्तेमाल पर काफी जोर दे रहे हैं. ऐसे में केले के पत्तों का उपयोग प्लास्टिक के विकल्प के रूप में करके अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है. दक्षिण भारत में तो केले के पत्तों की काफी डिमांड रहती है. सरकार की ओर से किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है. कृषि विभाग के अनुसार इस विधि से केले की खेती करने पर एक हैक्टेयर में करीब 1.25 लाख रुपए की लागत आती है. इसमें से 50 प्रतिशत सब्सिडी किसानों को दी जाती है. इस तरह किसान को सब्सिडी के तौर पर 62500 रुपए की सब्सिडी मिलती है. ऐसे में किसानों के लिए केले की खेती डबल मुनाफे का सौदा है. एक तो केले के फल बेचकर और दूसरा उनके पत्तों को बेचकर किसान कमाई कर सकते हैं.

इसके अलावा केले के पत्तों से ट्रे और प्लेट बनाने का बिजनेस शुरू करके भी अच्छी कमाई की जा सकती है.

साल के पत्तों की खेती

साल (शाल) के पेड़ के नाम से भी जाना जाता है. ये पेड़ हिमालय की तलहटी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उगता है. मुख्यतौर पर यह उत्तरप्रदेश, बिहार, बंगाल, झारखंड और असम छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जंगलों में पाया जाता है. यह पेड़ अत्यंत उष्ण और ठंडे स्थानों में आसानी से उगता है. इस पेड़ की लकड़ी काफी मजबूत होती है. इसलिए इसका उपयोग घर के दरवाजे व खिड़की के पल्ले बनाने, गाड़ी और छोटी नाव बनाने में किया जाता है. शाल के पत्तों का उपयोग भी केले के पत्ते की तरह भोजन परोसने में किया जाता है. एक अनुमान के मुताबिक यदि आप एक एकड़ में इसके 650 पौधे लगाते हैं. हालांकि इसके पेड़ों को तैयार होने में करीब 7 से 9 साल तक का समय लगता है. लेकिन पूर्णरूप से तैयार पेड़ों की लकड़ी और पत्तों को बेचने से काफी अच्छी कमाई होती है. इसके पौधे 100-200 रुपए प्रति नग के हिसाब से बिकते हैं. शाल की के पेड़ों की खेती भी किसानों के लिए लाभ का सौदा साबित हो सकती है.

करोड़ो रुपया, काली कमाई, एक जस्टिस और सीबीआई का फंदा

रायपुर. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज नारायण शुक्ला और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ नया केस दर्ज किया है. ये केस 2014 और 2019 के बीच आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में दर्ज हुआ है. सीबीआई की जांच में ये पाया गया कि जस्टिस शुक्ला के काले धन को दो ट्रस्टों, एक संस्था और रियल एस्टेट कंपनियों के जरिए सफेद किया गया. जस्टिस शुक्ला पर 2.5 करोड़ रुपये से ज्यादा इनकम के कई सबूत हाथ लगे हैं. पूर्व न्यायाधीश ने 1 अप्रैल, 2014 से 6 दिसंबर, 2019 तक 4.07 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की और खर्च किया. हालांकि, इसी अवधि में आय के सभी ज्ञात स्रोतों से शुक्ला की आय सिर्फ 1.53 करोड़ रुपये थी.

सीबीआई ने कहा कि सबसे पहले लखनऊ के गोल्फ सिटी इलाके में पूर्व न्यायाधीश और उनकी दूसरी पत्नी के घर और अमेठी में उनके बहनोई के आवास पर तलाशी ली गई. मामले की जांच के दौरान शुक्ला के मोबाइल फोन डेटा निकालने से सुचिता तिवारी से उसके संबंध का पता चला. यह सामने आया कि पूर्व न्यायाधीश ने पहली पत्नी सैदीन के नाम पर संपत्ति भी अर्जित की. बता दें कि शुक्ला के खिलाफ भ्रष्टाचार का ये दूसरा आरोप है. 2021 में शुक्ला के खिलाफ जांच एजेंसी ने लखनऊ के प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (पीआईएमएस) से जुड़े न्यायिक भ्रष्टाचार की जांच में आरोप पत्र दायर किया था.

रिटायर जज ने अपनी पत्नियों के नाम पर कमाया काला धन

सीबीआई ने बुधवार को दर्ज FIR में कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज एसएन शुक्ला ने सुचिता तिवारी (उनकी दूसरी पत्नी, जैसा कि सुचिता तिवारी ने सीबीआई अदालत में दायर अपने आवेदन में दावा किया है) और सैदीन तिवारी (शुक्ला की पहली पत्नी) के नाम पर धोखे से बहुत सारा अवैध धन कमाया. जांच एजेंसी ने एफआईआर में लिखा है कि अप्रैल 2014 और दिसंबर 2019 के बीच शुक्ला ने कुल 2,54,56,786 रुपये की आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित की है. दिलचस्प बात यह है कि पीआईएमएस रिश्वतखोरी कांड भी इसी दौरान हुआ था.

मेडिकल कॉलेज के पक्ष में आदेश पारित करने का है इल्जाम

जुलाई 2020 में रिटायर हुए जज शुक्ला पर लखनऊ के एक मेडिकल कॉलेज के पक्ष में एक आदेश पारित करने के लिए रिश्वत लेने का आरोप है. इस रिश्वतखोरी मामले में शुक्ला के अलावा ओडिशा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आईएम कुदुसी, भगवान प्रसाद यादव और प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट के पलाश यादव के अलावा एक मध्यस्थ भावना पांडे और एक बिचौलिये सुधीर गिरि पर जांच चल रही थी. कुल मिलाकर, प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट मामले में दो मामले दर्ज किए गए थे . पहला सितंबर 2017 में कुदुसी और बिचौलियों के नाम, और दूसरा दिसंबर 2019 में शुक्ला और दूसरे संदिग्धों के नाम.

पीआईएमएस रिश्वतखोरी कांड क्या है

सीबीआई ने 2021 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश श्री नारायण शुक्ला के खिलाफ एक निजी मेडिकल कॉलेज को लेकर कथित तौर पर रिश्वत लेने के लिए आरोप पत्र दायर किया गया था. शुक्ला के अलावा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश आई एम कुद्दुसी और तीन और व्यक्तियों के खिलाफ भी मामले में आरोपपत्र दाखिल किया गया था. मामले पर सीबीआई के एक अधिकारी ने कहा था कि, श्प्राथमिकी में जिन आरोपों का जिक्र किया गया है, उनकी पुख्ता सबूतों के जरिए पुष्टि हुई है. इसे लेकर साल 2021 में एजेंसी को शुक्ला के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी.

यह मामला 2017 के एक मामले से जुड़ा है . इसमें जांच एजेंसी ने कुद्दुसी को भी गिरफ्तार किया था. मामला दर्ज करने के समय मौजूदा न्यायाधीश शुक्ला को चार दिसंबर, 2019 को दर्ज प्राथमिकी में छह अन्य लोगों के साथ आरोपी बताया गया .

कुद्दुसी के अलावा उनकी सहयोगी भावना पांडे, प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट (पीईटी) की तरफ से संचालित लखनऊ स्थित मेडिकल कॉलेज प्रसाद इंस्टीटच्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के मालिक बीपी यादव और प्रसाद यादव और मेरठ में वेंकटेश्वर मेडिकल कॉलेज के मालिक सुधीर गिरि आरोपी ठहराए गए थे. सीबीआई की प्राथमिकी के मुताबिक, प्रसाद इंस्टीटच्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज उन 46 कॉलेजों में से एक था, जिन्हें सरकार ने 2017 में सुविधाओं की कमी की वजह से छात्रों को प्रवेश देने से रोक दिया था. ये रोक 2 साल के लिए लगी थी. एमसीआई के फैसले को प्रसाद इंस्टीटच्यूट ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. मामले पर सीबीआई ने कहा था कि एक साजिश के तौर पर इस मामले को हाईकोर्ट में पेश किया गया था. सीबीआई ने बताया था कि प्रसाद ट्रस्ट के कुद्दुसी और बीपी यादव ने 25 अगस्त, 2017 की सुबह लखनऊ में जज शुक्ला से उनके आवास पर मुलाकात की थी.

सीबीआई ने आरोप लगाया कि याचिका पर उसी दिन जज एसएन शुक्ला की पीठ ने सुनवाई की थी और उसके पक्ष में आदेश पारित किया. इसके बदले शुक्ला ने रिश्वत ली थी. ये रिश्वत 2 करोड़ की थी. पूर्व प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह की शिकायत पर शुक्ला के खिलाफ जांच का आदेश दिया था. तीन सदस्यीय समिति में मद्रास उच्च न्यायालय की तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी, सिक्किम उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एसके अग्निहोत्री और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पीके जायसवाल शामिल थे. शुक्ला को जनवरी 2018 में न्यायिक अनियमितताओं का दोषी पाया गया था, जिसके बाद भारत के राष्ट्रपति से उनके महाभियोग की सिफारिश की गई थी.

क्या होता है महाभियोग

महाभियोग वो प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजों को हटाने के लिए किया जाता है. इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 61, 124 (4), (5), 217 और 218 में मिलता है. महाभियोग प्रस्ताव सिर्फ तब लाया जा सकता है जब संविधान का उल्लंघन, दुर्व्यवहार या अक्षमता साबित हो गए हों. इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ के मौजूदा न्यायाधीश शुक्ला को अदालत परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया गया था और उनसे सभी न्यायिक और प्रशासनिक कार्य छीन लिए गए थे. जुलाई 2019 में पूर्व सीजेआई रंजन गोगोई ने सीबीआई को इस मामले में केस दर्ज करने की इजाजत दी थी. गोगोई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी पत्र लिखकर शुक्ला को हटाने की सिफारिश की थी. शुक्ला आखिरकार जुलाई 2020 में सेवानिवृत्त हुए.

एक नजर में शुक्ला पर लगे आरोपों की फेहरिस्त

- शिव शक्ति धाम ट्रस्ट से लाखों रुपये उनकी दूसरी पत्नी बताई जा रही सुचिता तिवारी को भजे गए.
- फैजाबाद अदद्भूत इंडिया अकादमिक फाउंडेशन ट्रस्ट से शुचिता तिवारी 2015 से 2017 के दौरान 2.84 लाख रुपये दिए गए.
- एंजेल ग्रुप ने भी 2015 से 2020 के दौरान शुचिता को 8, 62, 362 रुपये दिए.
- सीबीआई को शक है कि रकम शुक्ला की अवैध तरीके से कमाई गई रकम थी.

नई जांच में सीबीआई के हाथ क्या लगा

नया मामला आय से ज्यादा संपत्ति का है. जिसमें अभी जांच एजेंसी अमेठी की शिव शक्ति धाम ट्रस्ट, फैजाबाद की अदद्भूत इंडिया अकादमिक फाउंडेशन ट्रस्ट व एंजेल ग्रुप ऑफ एजूकेशन ट्रेनिंग समाज सेवी संस्थान के साथ एसएन शुक्ला के संबधों की पड़ताल कर रही है. पता चला है कि शुक्ला की दो रियल एस्टेट कंपनियों के जरिए कई बेनामी संपत्तियां भी खरीदी थी.

एयर इंडिया के बाद इंडिगो भी बड़ी संख्या में विमानों के आर्डर देने की तैयारी मे

एयर इंडिया के बाद भारत की सबसे बड़ी घरेलू बजट एयरलाइंस इंडिगो भी नए विमानों के खरीद के लिए आर्डर देने की तैयारी में है. इंडिगो विमानों के इस डील के लिए यूरोप की दिग्गज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एयरबस के साथ बातचीत कर रही है. ये खुलासा भारत में जी-20 के बैठक में शिरकत करने आए फ्रांस के वित्त मंत्री ब्रूनो ली मायर ने किया है.

फ्रांस की पब्लिकेशन ग्रुप Les Echos के मुताबिक इंडिगो के साथ एयरबस की ये डील फ्रांस के ली बारगेट में होने वाले फ्रेंच एयरशो में किया जाएगा. इस डील को लेकर एयरबस के प्रवक्ता ने रायटर्स को कहा कि कंपनी लगातार एयरलाइंस के साथ बातचीत करती रहती है. लेकिन उन्होंने किसी भी कंपनी का साथ किसी भी प्रकार की बातचीत पर कुछ भी बोलने से इंकार कर दिया. बीते हफ्ते ही टाटा समूह ने 470 नए विमानों का आर्डर बोइंग और एयरबस को दिया है. और कंपनी के पास इसके अतिरिक्त 370 और प्लेन के आर्डर करने का ऑप्शन उपलब्ध है. एक साथ इतनी बड़ी संख्या में विमानों का आर्डर देने का ये वर्ल्ड रिकार्ड है जो पहले अमेरिकन एयरलाइंस के नाम था जिसने 2011 में 460 विमानों का आर्डर एक साथ दिया था.

इंडिगो मौजूद समय में देश की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइंस है. लेकिन आने वाले दिनों में उसे टाटा समूह के एयर इंडिया से उसके वर्चस्व को जबरदस्त चुनौती मिलने वाली है. एयर इंडिया विस्तारा, एयरएशिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस का आपस में विलय कर बड़ी एयरलाइंस कंपनी तैयार करने जा रही है. इसी चुनौती का सामना करने के लिए अब इंडिगो भी तैयारी में जुट गई है. सरकार अगले 5 वर्षों में 80 नए एयरपोर्ट बनाने जा रही है जिसके बाद देश में कुल 220 एयरपोर्ट हो जायेंगे. बोईंग की रिपोर्ट के मुताबिक 2041 तक भारत में हर साल 7 फीसदी के दर से पैसेंजर ट्रैफिक बढ़ने का अनुमान है. भारत में बढ़ते एयर ट्रैवल की मांग को पूरा करने के लिए घरेलू एयरलाइंस कंपनियों को 2210 नए प्लेन का आर्डर करना पड़ सकता है.

7 हजार से भी कम में तगड़े फीचर्स के साथ Nokia C02 हुआ लॉन्च

नोकिया सी सीरीज के अंतर्गत ग्राहकों के लिए नया अर्फोडेबल स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है. Nokia C02 मोबाइल फोन को कंपनी ने कम बजट वाले ग्राहकों को ध्यान में रखते हुए उतारा है, बता दें कि इस नोकिया स्मार्टफोन में आप लोगों को एंट्री लेवल स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेंगे. आइए आप लोगों को Nokia C02 की कीमत से लेकर फीचर्स तक की विस्तार से जानकारी देते हैं. इस नोकिया स्मार्टफोन के दो कलर वेरिएंट्स उतारे गए हैं, चारकोल और डार्क सेयान. फिलहाल इस डिवाइस की कीमत और उपलब्धता के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इस हैंडसेट की कीमत 80 डॉलर (लगभग 6619 रुपये) हो सकती है.

तो अगर आप भी नोकिया ब्रांड कंपनी के चाहने वाले हैं, और आप नोकिया पर भरोसा करते हैं तो आपको नोकिया का यह फोन एक बार जरूर देखना चाहिए. क्योंकि नोकिया के फोन शुरुआती दौर में बहुत ही भरोसेमंद माने जाते थे लेकिन समय के अनुसार उन्होंने अपने बदलाव ना करने के कारण यह कंपनी धीरे-धीरे समाप्त होने के कगार पर आ गई थी लेकिन अब फिर से नोकिया ने अपने मोबाइल इंडस्ट्री में कदम रखा है और यह तेजी से अब आगे बढ़ता चला जा रहा है.

Nokia C02 Specifications

नोकिया C02 में 5.45 इंच LCD FWVGA+ डिस्प्ले दी गई है. स्क्रीन का आस्पेक्ट रेशियो 18:9 है. हैंडसेट में डिस्प्ले पर चारों तरफ मोटे बेजल दिए गए हैं. स्मार्टफोन को पॉलीकार्बोनेट फ्रेम के साथ लॉन्च किया गया है और इसमें रियर पर नैनो-टेक्स्चर मिलता है. फोन में IP52 रेटिंग है यानी यह वॉटरप्रूफ हैंडसेट है.

कैमरा सेटअपः इस नोकिया मोबाइल फोन के बैक पैनल पर एलईडी फ्लैश के साथ 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा सेंसर दिया गया है तो वहीं फ्रंट में 2 मेगापिक्सल का कैमरा सेंसर सेल्फी लवर्स के लिए मौजूद है.

बैटरी क्षमताः नोकिया सी02 स्मार्टफोन में कंपनी ने 3000 एमएएच की बैटरी फोन में जान फूंकने के लिए दी है.

चिपसेट, रैम और स्टोरेजः स्पीड और मल्टीटास्किंग के लिए 1.4 गीगाहर्ट्ज क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है. इस डिवाइस में 2 जीबी रैम के साथ 32 जीबी की इंटरनल स्टोरेज दी गई है.

सॉफ्टवेयरः नोकिया सी02 में दिए गए ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये फोन एंड्रायड 12 गो एडिशन पर काम करता है. इस डिवाइस को 2 सालों तक सिक्योरिटी अपडेट्स मिलने की गारंटी भी दी गई है.

कनेक्टिविटी विकल्पों की बात करें, तो फोन में वाई-फाई, ब्लूटूथ 4.2, माइक्रो-यूएसबी पोर्ट, 3.5 मिमी ऑडियो जैक है. इसमें फेस अनलाकिंग की सुविधा भी है. कंपनी का कहना है कि फोन को 2 साल तक तिमाही सुरक्षा अपडेट मिलेंगे. इसे चारकोल ग्रे और डार्क सियान रंग विकल्पों में पेश किया गया है. उम्मीद है कि इसकी बिक्री Nokia-com व अन्य पार्टनर रिटेल स्टोर्स के माध्यम से शुरू होगी.

व्हाट्सएप में भेजे हुए मैसेज को कर सकेंगे एडिट

कई बार हम व्हाट्सएप पर कोई मैसेज भेजकर ये सोचते हैं कि काश हम इसे एडिट कर पाते. एक छोटे से एडिट के लिए भी हमें मैसेज को डिलीट करके वापस से भेजना पड़ता है. हालांकि, जल्द ही आपके पास एक नया फीचर आने वाला है. इस फीचर से आप व्हाट्सएप मैसेज को बिना डिलीट किए उसमें सुधार कर सकेंगे या उसे एडिट कर सकेंगे. उसे एडिट करने के लिए आपको 15 मिनट का समय मिलेगा. मेटा के मुताबिक, वह इस फीचर पर काम कर रहा है. दरअसल, ये जानकारी WABetaInfo पर शेयर की गई है. जिसमें निम्नलिखित स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है-

जैसा कि ऊपर फोटो में दिखाया गया है, अगर आप पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं जिसमें ये फीचर नहीं चलेगा तो यूजर को मैसेज मिलेगा. इसके लिए बस आपको व्हाट्सएप के वर्जन को ऐप स्टोर या टेस्टफ्लाइट पर उपलब्ध लेटेस्ट अपडेट में अपडेट करना होगा.

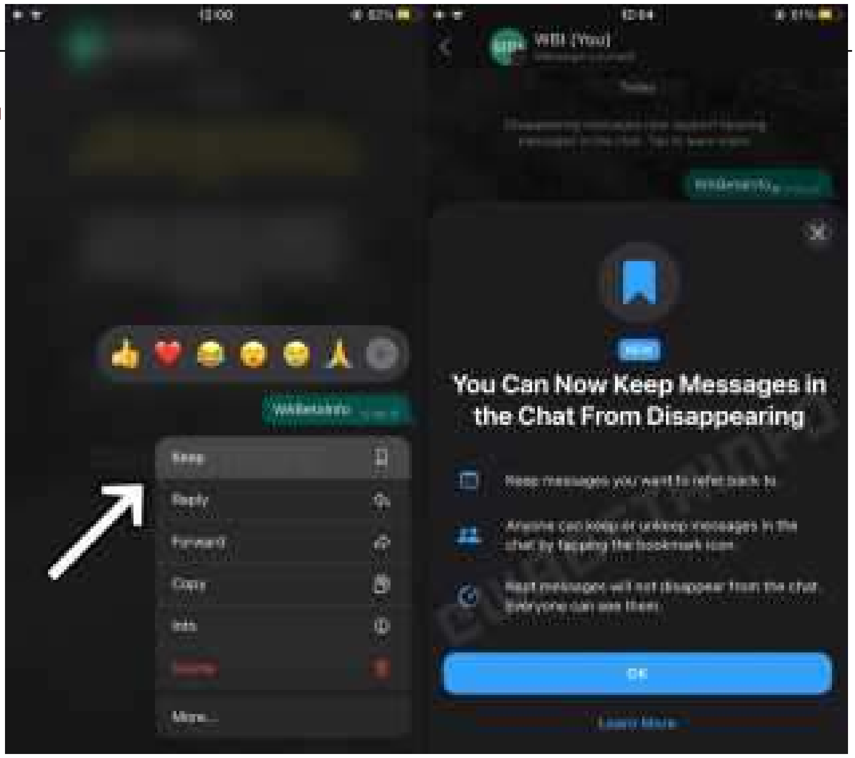

15 मिनट के भीतर कर सकेंगे एडिट

बताते चलें भेजे गए मैसेज को आप 15 मिनट के भीतर एडिट कर सकते हैं. वर्तमान में, अगर आप व्हाट्सएप का पुराना वर्जन चला रहे हैं, तो एडिटेड मैसेज दिखाई नहीं देगा, लेकिन यूजर को एक वार्निंग मैसेज मिलेगा कि व्हाट्सएप का उनका अपडेट नए फीचर को सपोर्ट करता है या नहीं.

गौरतलब है कि डेवलपर्स कथित तौर पर एक दूसरे फीचर पर भी काम कर रहे हैं जिनसे वे मीडिया कैप्शन भी एडिट कर सकते हैं. चूंकि, अभी एडिटिंग फीचर को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है इसलिए यह कहना काफी मुश्किल है कि ये कबतक उपलब्ध होगा.

चलाते हैं डीजल कार तो मेंटेनेंस के लिए जरूर ध्यान रखें ये 5 बाते

डीजल इंजन की मेंटेनेंस के वक्त कई बातों का ध्यान रखना होता है. अगर आप इसकी मेंटेनेंस करवाते समय लापरवाही बरतते हैं तो आपकी गाड़ी के इंजन को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है. अगर आप मेंटेनेंस के वक्त ऑयल और एयर फिल्टर साफ नहीं करवाते हैं तो आपका इंजन समय से पहले खराब हो सकता है. इन्हें तय वक्त पर साफ करवाते रहें. इससे इंजन की लाइफ तो बढ़ेगी ही साथ ही इसकी परफार्मेंस में भी सुधार होगा. आज हम आपको उन बातों के बारे में बता रहे हैं जिनका आपको इंजन की मेंटेनेंस करवाते समय ध्यान रखना चाहिए.

एयर फिल्टर की सफाई करें या बदल दे

एयर फिल्टर पर गंदगी जमी रहने से वाहन का परफार्मेंस खराब हो जाता है. ऐसे में इसकी नियमित सफाई जरूरी है. अगर आपको लगता है कि एयर फिल्टर अब उपयोग करने लायक नहीं है तो इसे तुरंत बदल दें. साफ एयर फिल्टर के चलते इंजन की परफार्मेंस बेहतर हो जाएगी.

ऑयल फिल्टर का रखें ध्यान

अधिकांश डीजल इंजनों में गैस टैंक और इंजन के बीच और फ्यूल फिल्टर, पंप और फ्यूल इंजेक्टर के बीच दो फ्यूल फिल्टर लगे होते हैं, जो फ्यूल साफ करने का काम करता है. इनमें धीरे-धीरे काफी गंदगी जमा हो जाती है, जिसे साफ कराते रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो गाड़ी के इंजन को नुकसान पहुंच सकता है.

ऑयल चेंज

डीजल इंजन को सही रखने के लिए लुब्रिकैंट का इस्तेमाल किया जाता है और आपको समय-समय पर इंजन ऑयल और ऑयल फिल्टर बदलना चाहिए. जब आपकी कार का ऑयल काला पड़ जाए, तो उसे तुरंत बदल देना चाहिए. इसके साथ ही इंजन ऑयल को जरूरत पड़ने पर टॉप-अप भी करवाते रहना चाहिए. अगर आपकी कार का इंजन ऑयल बार-बार काला पड़ रहा है, तो उसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करें.

इंजन की साफ-सफाई

पूरे इंजन की साफ-सफाई करते रहें. इससे इस पर धूल-मिट्टी नहीं जमेगी और इसके सारे पार्ट्स सही से काम करते रहेंगे.

कूलैंट चेक करे

पेट्रोल इंजन की जगह डीजल इंजन काफी जल्दी गर्म हो जाता है है. कई बार इंजन ओवरहीटिंग के भी शिकार भी हो सकता है. इस दौरान कूलैंट का काम काफी महत्वपूर्ण हो जाता है. कूलैंट को समय-समय पर चेक करते रहें. कूलैंट कम रहने पर उसे डलवा लें. इस दौरान ये ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि की इंजन का कूलैंट लीक तो नहीं हो रहा है. ऐसी स्थिति आने पर कूलैंट को तत्काल सही कराएं. देरी करने पर इंजन को भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है.

टाटा ने लॉन्च किया एक साथ 3 दमदार SUVs

मुंबई. टाटा मोटर्स ने अपनी Nexon, Harrier और Safari एसयूवी का रेड डार्क एडिशन लॉन्च किया है. इस नए वेरिएंट को रेग्युलर मॉडल की तुलना में ज्यादा बेहतर स्टाइल और ADAS समेत ज्यादा फीचर्स के साथ लाया गया है. नेक्सान रेड डार्क एडिशन पेट्रोल और डीजल दोनों विकल्पों में उपलब्ध है, जबकि हैरियर और सफारी रेड डार्क एडिशन सिर्फ डीजल इंजन में आती है. इन कारों की बुकिंग आज से ही 30 हजार रुपये में शुरू हो गई है.

रेड डार्क एडिशन में क्या होगा खास

लाल हाइलाइट्स के साथ ओबेरॉन ब्लैक एक्सटीरियर ह्यू, जिरकॉन रेड एक्सेंट्स के साथ पियानो ब्लैक फ्रंट ग्रिल, फ्रंट फेंडर्स पर श्रेड डार्कश् बैजिंग इस एडिशन के वाहन के लुक को और शानदार बनाएंगे. साथ ही इस एडिशन के वाहनों में ब्रेक कैलीपर्स के साथ चारकोल ब्लैक फिनिश में 18 इंच के डायमंड-कट अलॉय व्हील दिए जाएंगे. रेड डार्क एडिशन के वाहनों के हेडरेस्ट पर "डार्क" लोगो, रेड ग्रैब हैंडल, डायमंड - स्टाइल क्विल्टिंग लेदर सीट मिलेगा. साथ ही कार्नेलियन रेड इंटीरियर थीम, एक नया 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 360-डिग्री व्यू कैमरा भी मिलेगा.

10 नए ADAS फीचर्स से लैस

रेड डार्क एडिशन एसयूवी के खासियत की बात करें तो इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर में न्यू कार्नेलियन रेड हाइलाइट्स देखने को मिलता है, जो कारों के प्रीमियम वाइब को और ज्यादा बढ़ाता है। SUVs 26.03 सेमी डिस्प्ले साइज और 10 नए ADAS फीचर्स के साथ आती हैं. इनमें एक बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा. वाहन निर्माता का दावा है कि सभी नई एसयूवी न्यू BS6 फेज-2 एमिशन नार्म्स का पालन करती हैं. कॉस्मेटिक अपडेट और न्यू फीचर्स अपडेट के अलावा SUVs में किसी तरह का मैकेनिकल बदलाव नहीं किया गया है.

कीमत की बात करें तो Nexon पेट्रोल रेड डार्क एडिशन की कीमत 12.35 लाख रुपये है, और डीजल वेरिएंट की कीमत 13.70 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. जबकि टाटा हैरियर Red Dark Edition की कीमत 21.77 लाख रुपये है, और सफारी Red Dark Edition की कीमत क्रमशः 6-सीटर के लिए 22.71 लाख रुपये और 7-सीटर वेरिएंट के लिए 22.61 लाख रुपये है.

पेंशन बढ़ाने का आवेदन 3 मई तक कर सकेंगे

> मुंबई. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के सदस्यों को अधिक पेंशन का विकल्प चुनने के लिए अधिक समय मिल सकेगा. पात्र सदस्य अब अपने नियोक्ता के साथ संयुक्त रूप से इस विकल्प को चुनने के लिए तीन मई 2023 तक आवेदन कर सकते हैं.

इससे पहले उच्चतम न्यायालय के चार नवंबर 2022 के आदेश के मुताबिक सभी पात्र सदस्यों को ऊंची पेंशन का विकल्प चुनने के लिए चार महीने का समय दिया गया था. यह चार माह की अवधि तीन मार्च 2023 को समाप्त हो रही है. लेकिन ईपीएफओ के एकीकृत सदस्य पोर्टल पर हाल में सक्रिय किए गए यूआरएल लिंक से स्पष्ट हुआ है कि विकल्प चुनने की अंतिम तिथि तीन मई है. पिछला बकाया भी देना होगा इस योजना के तहत राशि का जो अंतर आएगा वह आपके पीएफ खाते से कट जाएगा.

यूएएन पोर्टल पर जाएं कर्मचारी ईपीएफओ की इस खास सुविधा के तहत यूएएन पोर्टल पर लॉग इन कर सकते हैं. पात्र कर्मचारी पोर्टल पर जाकर आवेदन जमा कर सकते हैं. विशेषज्ञों के अनुसार 25 से 35 साल के युवाओं के लिए यह फायदेमंद है. वहीं, सेवानिवृत्ति के पांच साल पहले वेतन का एक बड़ा हिस्सा इस योजना में लगाना होगा.

यह होगी प्रक्रिया

संयुक्त रूप से ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन की रसीद संख्या दी जाएगी. प्रभारी जांच करेंगे और निर्णय की सूचना देंगे. पोर्टल पर शिकायत दर्ज की जा सकती है. पात्र को संयुक्त रूप से आयुक्त द्वारा निर्धारित आवेदन और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना हो

ये आवेदन कर सकेंगे

जिन्होंने 5,000 रुपये या 6,500 रुपये की तत्कालीन वेतन सीमा से अधिक वेतन में योगदान दिया था. ईपीएस सदस्य होने के दौरान पिछली विंडो में संयुक्त विकल्प का इस्तेमाल नहीं किया. ऐसे सदस्य, जो 1 सितंबर 2014 से पहले या बाद में ईपीएस के सदस्य थे. कर्मचारी पेंशन योजना के तहत अभी 15 हजार रुपये तक के वेतन के हिसाब से पेंशन फंड में अंशदान तय होता है. यानी कि बेसिक वेतन 50 हजार रुपये हो जाए तो भी ईपीएस में अंशदान 15 हजार रुपये के हिसाब से ही तय होता है. इससे कर्मचारी ईपीएस में काफी कम रुपये जमा हो पाते हैं. इससे कम पेंशन बन पाती है लेकिन अब इस सीमा को बढ़ा दिया गया है.

मसालों की खेती में छत्तीसगढ़ की बन रही देश में नई पहचान

छत्तीसगढ़ में मसालों की खेती का दायरा बढ़ते जा रहा है. राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों का खेती-किसानी के क्षेत्र में असर दिख रहा है. किसान नवाचार की ओर बढ़ रहे हैं. सामान्यतः छत्तीसगढ़ में जो किसान धान तथा अन्य परम्परागत फसलों की खेती करते रहे हैं, वे अब मसालों की खेती की ओर भी रूख कर रहे हैं. मसालों की खेती में छत्तीसगढ़ की देश में नई पहचान बन रही है.

छत्तीसगढ़ की जलवायु और मिट्टी मसालों की खेती के अनुकूल होने के कारण उत्पादन भी अच्छा हो रहा है. राज्य के किसानों को उत्पादन के साथ-साथ अच्छी आमदनी भी मिल रही है. छत्तीसगढ़ में मसालों की मांग और आपूर्ति में संतुलन की स्थिति आ रही है. इस समय मसालों का उत्पादन चार लाख मीट्रिक टन से भी अधिक है. साथ ही इस क्षेत्र में इतने उत्साहजनक परिणाम मिल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से धनिया के भी बीज अन्य राज्यों को आपूर्ति की जा रही हैं.

कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार छत्तीसगढ़ की जलवायु मसालों के उत्पादन के अनुकूल है. इसलिए यहां मसालों की खेती लगातार बढ़ती जा रही है. हल्दी, अदरक, लाल मिर्च, अजवाईन, ईमली, लहसून की खेती की जा रही है. हल्दी, धनिया, मेथी, लहसून, मिर्च, अदरक की खेती छत्तीसगढ़ के करीब-करीब सभी क्षेत्रों में की जा रही है. वहीं बलरामपुर, बिलासपुर, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही और मुंगेली में अजवाइन तथा कोंडागांव में काली मिर्च की खेती भी की जा रही है.

हल्दी का उत्पादन सर्वाधिक

मसालों की खेती के रकबे के साथ-साथ उत्पादन में भी तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है. छत्तीसगढ में अभी 66081 हेक्टेयर में मसालों की खेती हो रही है और लगभग 4 लाख 50 हजार 849 मीट्रिक टन मसालों का उत्पादन हुआ है. छत्तीसगढ़ में हल्दी का रकबा और उत्पादन सबसे अधिक है. उसके बाद अदरक, धनिया, लहसून, मिर्च, इमली की खेती की जा रही है.

योजनाओं से मिल रही मदद

मसाले की खेती के लिए किसानों को राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय कृषि योजना तथा अन्य योजना के तहत सहायता दी जाती है. राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत 24 जिलों में मसाले की खेती 13302 हेक्टेयर में की गई है और 93114 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ है. वही राज्य में संचालित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत विगत चार वर्षों में 1837.29 हेक्टेयर में मसाले की खेती की गई एवं औसतन 12861 मीट्रिक टन का उत्पादन प्राप्त हुआ है. इससे लगभग 3500 कृषक लाभान्वित हुए हैं.

किसानों को मिल रही भरपूर आमदनी

धनिया की खेती करने वाले कृषक मयंक तिवारी बताते हैं कि एक हेक्टेयर में बोने पर लगभग 20 हजार रूपए का खर्च आता है. फसल होने पर 60 से 65 हजार तक की आमदनी प्राप्त की जा सकती है. उन्होंने बताया कि सभी खर्च काटकर 40 से 45 हजार की शुद्ध आमदनी होती है.

बलौदाबाजार जिले में हल्दी की खेती करने वाली महिला स्व-सहायता समूह की अध्यक्ष लोकेश्वरी बाई ने बताया कि एक एकड़ में हल्दी लगाई है जिस पर 50,000 रूपए का लागत लगी है. फसल काफी अच्छी हुई तथा औसत उत्पादन 50-60 क्विंटल प्राप्त होने की सम्भावना है जिसमे से 5 क्विंटल की खोदाई हो गयी है जिसे पीसकर पैकिंग कर किराना दुकान में बेच रहे हैं जिससे 60-65 हजार की आमदनी हुई है.

राजनांदगांव की कृषक अरपा त्रिपाठी, गोपाल मिश्र, संजय त्रिपाठी और जैनु राम ने मिलकर 12.208 हेक्टेयर में हल्दी की खेती की है. उन्हें 250-300 मीट्रिक टन उत्पादन प्राप्त होने की सम्भावना है.

कोरबा जिले के कृषक प्रताप सिंह ने बताया कि उन्होंने 0.400 हेक्टेयर में अदरक की फसल बोई जिसमें 90 हजार रूपए की लागत आई. लगभग 47 क्विंटल उत्पादन हुआ, इसे बेचने पर उन्हें 1.40 लाख रूपए मिले. इस राशि में उन्हें 50 हजार रूपए का शुद्ध फायदा हुआ. बीते चार सालों में लगभग 300 किसानों को अदरक की खेती के लिए प्रशिक्षण दिया गया है. इन किसानों ने 130 हेक्टेयर में अदरक की खेती कर 2000 टन अदरक का उत्पादन किया है.

मसालों की नई किस्म पर शोध

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक एस.एच. टूटेजा ने बताया कि बीते सालों में मसालों के बीजों पर शोध किया जा रहा है जिसमें धनिया की दो किस्में सीजी धनिया व सीजी चन्द्राहु धनिया विकसित की गई जिससे अच्छी फसल प्राप्त हो रही है. इसकी स्थानीय स्तर के अलावा अन्य 7 राज्यों में आपूर्ति की जा रही है. इसी तरह हल्दी की भी नई किस्म विकसित की गई है. श्री टूटेजा ने बताया कि छत्तीसगढ़ में मसाला फसलों की बहुत अच्छी संभावना है. अब किसान जागरूक होकर इसकी खेती कर रहे हैं और अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं.

नौकरी से रिटायरमेंट प्लानिंग में इन योजनाओं को करें शामिल

यदि आप अभी से सही तरीके से निवेश करें तो रिटायरमेंट के बाद आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी. हम आपको कुछ ऐसी सरकारी स्कीमों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें हर महीने बचत करके आप अच्छा फंड जमा कर सकते हैं. इन योजनाओं में निवेश करके आप हर महीने इनकम पा सकते हैं. पेंशन की चिंता नहीं रहेगी.

एनपीएस

एनपीएस एक टैक्स सेविंग रिटायरमेंट स्कीम है. इसे सरकार की ओर से केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्ष 2004 में लॉन्च किया गया था, जिसे 2009 में सभी नागरिकों के लिए खोल दिया गया. एनपीएस को इस तरह से बनाया गया, जिससे निवेश करने वाले लोगों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन के साथ अच्छा रिटर्न मिल सके. एनपीएस में किसी भी निवेशक को कम से कम 6000 रुपए प्रतिवर्ष का निवेश करना होता है और उसे रिटायरमेंट तक इस निवेश को जारी रखना होता है. रिटायरमेंट पर निवेशक 60 प्रतिशत तक ही पैसे की निकासी कर सकते हैं. बाकी का 40 प्रतिशत पैसा दोबारा से निवेश कर दिया जाता है, जिससे एनपीएस होल्डर को पेंशन दी जा सके.

इस तरह हर महीने मिलेगी हजारों रुपए की पेंशन

मान लीजिए अभी किसी की उम्र 25 साल है और वो रिटायरमेंट के बाद 75 हजार रुपए की पेंशन पाना चाहता है. इसके लिए उसे अभी से एनपीएस में हर महीने 10 हजार रुपए का निवेश करना होगा. यह निवेश उसे अगले 35 साल तक एनपीएस में करना होगा. ऐसा करने पर सालाना 10 फीसदी रिटर्न पर उसका कुल एनपीएस इनवेस्टमेंट मैच्योरिटी पर 3,82,82,768 रुपए होगा. यहां हम यह मानकर चल रहे हैं कि एनपीएस कॉर्पस का केवल 40 फीसदी अनिवार्य हिस्सा ही एन्युटी खरीदने में निवेश होगा. अगर वह ऐसा करता है तो उसे रिटायरमेंट के बाद हर महीने 76,566 रुपए पेंशन मिलेगी.

सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम

इस स्कीम का लाभ 60 साल की उम्र वाले या फिर उससे ज्यादा की उम्र वाले लोग ले सकते हैं. इस स्कीम में 30 लाख रुपए तक का निवेश किया जा सकता है. इसमें टैक्स बेनेफिट आयकर की धारा 80सी के तहत दी जाती है. यह स्माल सेविंग स्कीम के तहत संचालित की जाती है.

प्रधानमंत्री वय वंदना योजना

इस स्कीम के तहत पेंशन के साथ ही इंश्योरेंस का भी लाभ मिलता है. सीनियर सिटीजन एलआईसी के तहत ये इस स्कीम में निवेश कर सकते हैं. इसमें 15 लाख रुपए तक निवेश किया जा सकता है. हालांकि इस स्कीम में निवेश करने का लास्ट समय 31 मार्च 2023 है. इसमें 7.4 फीसदी का सालाना ब्याज 10 सालों तक दिया जाता है.

अटल पेंशन योजना

भारत सरकार देश के तमाम लोगों को बुढ़ापे में रेगुलर इनकम की चिंता से मुक्त करने के लिए अटल पेंशन योजना चलाती है. भारत सरकार के इस पेंशन स्कीम में 18 साल से लेकर 40 साल से कम उम्र के कोई भी लोग निवेश कर सकते हैं. जो लोग टैक्सपेयर्स नहीं हैं, वे इस स्कीम में योगदान कर सकते हैं. इस स्कीम के तहत मंथली पांच हजार रुपए की पेंशन ले सकते हैं.

60 साल बाद नए अवतार में आया Nokia

फिनलैंड की स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Nokia ने एक नए लोगो के साथ अपने ब्रांड की पहचान बदलने का प्लान बनाया है. अब आपको कंपनी के नीले रंग वाले लोगो की जगह नए कलेवर वाला लोगा दिखेगा. कंपनी ने इस लोगो का ऐलान मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2023 के दौरान किया है. कंपनी ने अपने लोगो को 60 साल बाद बदला है. इससे पहले कई बार इसमें थोड़े बहुत बदलाव होते रहे हैं लेकिन पहली बार इसे पूरी तरह से बदला गया है. मार्केट में इसे मोबाइल कंपनी के कमबैक की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है.

अन्य नेटवर्क बिजनेस पर भी फोकस करने की तैयारी

नए लोगो में पांच अलग-अलग साइज शामिल हैं जो NOKIA शब्द बनाते हैं. इस्तेमाल के हिसाब से कलर्स की एक सीरीज के लिए पुराने लोगो के लोकप्रिय ब्लू कलर को हटा दिया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी अपना लोगो बदलने के साथ-साथ मोबाइल बिजनेस के अलावा अन्य नेटवर्क बिजनेस पर भी फोकस करने की तैयारी में है. गौरतलब है कि नोकिया स्मार्टफोन्स के अलावा 5G इक्विपमेंट्स बनाने का भी काम करती है.

एचएमडी ग्लोबल के पास मोबाइल कारोबार

अगर नोकिया मोबाइल ब्रांड की बात की जाए तो मोबाइल फोन बनाने का लाइसेंस HMD ग्लोबल के पास है. नोकिया के लोगो के बदलने के बाद भी HMD ग्लोबल पुराने क्लासिक लोगो के साथ ही फोन की बिक्री करेगी. 2014 में नोकिया का मोबाइल व्यवसाय खरीदने वाली माइक्रोसाफ्ट की ओर से नाम का उपयोग बंद करने के बाद एचएमडी को लाइसेंस मिला.

आज कंपनी का व्यवसाय बदल गया है

नए लोगो के बारे में बताते हुए कंपनी के सीईओ पेक्का लुंडमार्क ने बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस (MWC) के एक दिन पहले एक इंटरव्यू में कहा कि यह स्मार्टफोन से कंपनी के जुड़ाव को दिखाता था, लेकिन आज कंपनी का व्यवसाय बदल गया और टेक्नोलॉजी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. काफी सारे लोगों के दिमाग अभी नोकिया की छवि एक सफल मोबाइल ब्रांड की हैं, लेकिन नोकिया वह नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि एक नया ब्रांड जो नेटवर्क और औद्योगिक डिजिटलीकरण पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है, जो विरासत मोबाइल फोन से बिल्कुल अलग है. लुंडमार्क ने कहा कि संकेत बहुत साफ है. हम सिर्फ ऐसे बिजनेस में रहना चाहते हैं जहां हम ग्लोबल लीडरशिप देख सकें.

नोकिया ने हाल ही में लॉन्च किया था फोन

नोकिया ने हाल ही में Nokia G22 स्मार्टफोन को लॉन्च किया है इस मोबाइल फोन की खास बात ये रही कि इसका बैक कवर 100% रीसाइकिल्ड प्लास्टिक से बना हुआ है. इसकी बैटरी, डिस्प्ले, चार्जिंग पोर्ट हर चीज को ग्राहक घर पर ही ठीक कर सकते हैं. इसके लिए कंपनी आपको मोबाइल फोन के साथ iFixit किट फ्री में दे रही है. इससे आप स्मार्टफोन का कोई भी पार्ट आसानी से बदल सकते हैं.

भारत में मिली सोने की खान

लिथियम के बाद गोल्ड करेगा इंडिया को मालामाल

"रायपुर. जम्मू कश्मीर में लिथियम का खजाना मिलने के बाद अब भारत के लिए एक और बड़ी खबर है. देश के 3 जिलों में सोने के भंडार मिले हैं. एएनआई की खबर के मुताबिक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपने सर्वे में पाया है कि ओडिशा के तीन जिलों में सोने का भंडार पाया गया है. ओडिशा के खनन मंत्री प्रफुल्ल मलिक ने जानकारी दी है कि यह रिजर्व देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज जिलों में पाया गया है."

विधानसभा में विधायक सुधीर कुमार सामल के सवाल के लिखित जवाब में मंत्री प्रफुल्ल मलिक ने कहा कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और राज्य के खनन और भूविज्ञान निदेशालय ने अपने सर्वेक्षण में पाया है कि सोने के भंडार पाए गए हैं. देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज जिले. है.

सोने के भंडार कहां मिले थे ?

गौरतलब है कि यह गोल्ड रिजर्व मयूरभंज में चार जगहों पर, देवगढ़ में एक जगह और क्योंझर में चार जगहों पर मिला है. इसमें मयूरभंज जिले के सुरियागुड़ा, रुआंसिला, धुशूरा पहाड़ी और जोशीपुरा क्षेत्र शामिल हैं. यह भण्डार देवगढ़ के अदास और क्योंझर के डिमिरिमुण्डा, कुशकला, गोटीपुर और गोपुर में पाया गया है. इसके साथ ही प्रफुल्ल मलिक ने अपने जवाब में यह भी कहा कि इन इलाकों में साल 1970 और 1980 में जीएसआई सर्वे कराया गया था, लेकिन उसका रिजल्ट जारी नहीं किया गया. लेकिन पिछले 2 साल से जीएसआई इन तीनों जिलों में लगातार सर्वे कर रहा था. इसके बाद पता चला कि इन जगहों पर सोने के भंडार हैं. फिलहाल अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि इन तीनों जिलों में मिला सोने का भंडार कितना बड़ा है और इसमें कितना सोना मौजूद है.

पहले लिथियम के भंडार भारत में पाए जाते थे

सोने से पहले देश में पहली बार लिथियम के भंडार मिले थे. यह स्टोर जम्मू-कश्मीर के रियासी में मिला था. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई के मुताबिक यह रिजर्व 59 लाख टन का है.

इतनी बड़ी मात्रा में लीथियम मिलने के बाद अब भारत को इसके लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. आपको बता दें कि लिथियम एक सफेद रंग की धातु है जिसका इस्तेमाल ज्यादातर बैटरी बनाने में किया जाता है. ऐसे में इसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है.

Toll Free No. : 1800 102 6415 | Website : www.chhattisgarhtourism.in | Follow us on :

छत्तीसगढ़ मॉडल
अंतिम व्यक्ति तक न्याय

107.53 लाख मीट्रिक टन
धान खरीदी का कीर्तिमान

लघु वनोपज
खरीदी में
देश में अव्वल

छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को दिए
150,000 करोड़ रुपए

गोधन न्याय योजना के तहत सरकार द्वारा गोबर और गौमूत्र की खरीद से
मजबूत ग्रामीण अर्थव्यवस्था

जंगल, गांव, बस्ती में मोबाइल अस्पतालों से **1.22 करोड़** लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं

वन आश्रितों को वनाधिकार देने में
देश में अव्वल

देश में मिसाल बने स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट स्कूलों में सभी वर्ग के **2.5 लाख** से ज्यादा बच्चों को आधुनिक शिक्षा के अवसर

दवाइयों पर **70 प्रतिशत** तक की छूट से 85 करोड़ रुपए की बचत

45 लाख उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर 3,250 करोड़ रुपए की राहत

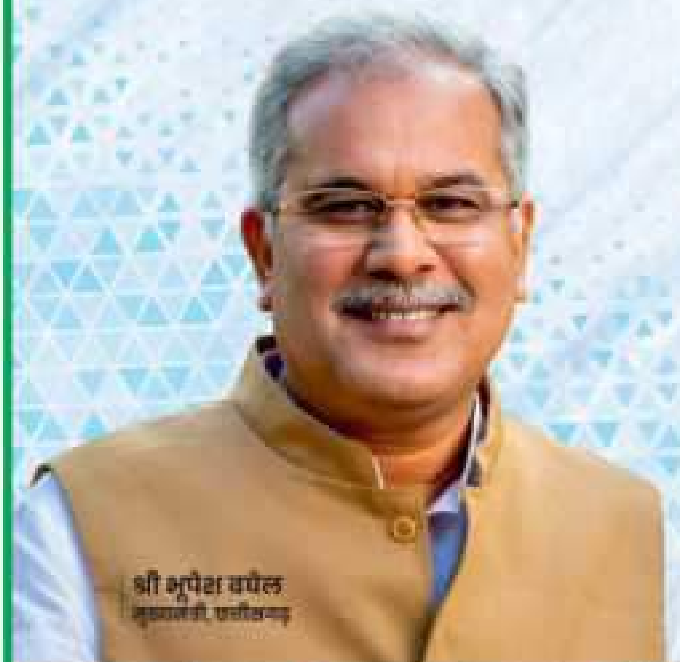

Visit us : ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh DPRChhattisgarh

R.O. No. - 12350/123